संयम ◆ संस्कार ◆ संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-21 अंक- 186
पृष्ठ 8
गुरूवार
27 मार्च 2025
प्रात: संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- ये लोग बिलकुल ना पीएं कॉफी...
विचार- कटाक्षों से घबराती सरकार
खेल- जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगे...

घबराइए मत, हर समस्या का होगा समाधान : योगी

गोरखपुर, संवाददाता। अपने नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 8 सफल वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, एक विशेष समारोह में शामिल होने के लिए मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात निवास करने के बाद, बुधवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा, 'घबराइए मत, हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. हर पीड़ित की शिकायत का प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा.' जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निस्तारण कराएं। गोरखनाथ मंदिर मीडिया सेल से जारी खबर के अनुसार आज सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने, आयोजित

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए. जनता दर्शन में महिलाओं की संख्या अधिक रही, कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे. एक–एक कर और इत्मीनान से सबकी समस्याएं

● जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं

● अधिकारियों से बोले सीएम, हर पीड़ित की समस्या का हो समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

सुनीं. उन्हें आश्वस्त किया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए. कुछ लोगों के तहत जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश भी दिए कि यदि किसी प्रकरण में पीड़ित को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो इसकी भी जांच कर जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी, बाधक नहीं होगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में परिजनों के साथ बच्चों पर खूब प्यार–दुलार बरसाया. उन्होंने इन बच्चों से बात कर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट गिफ्ट करते हुए आशीर्वाद दिया।

सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिला, मौत की फिर से होनी चाहिए जांच

● सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के बाद भाजपा एमएलए की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर भाजपा विधायक राम कदम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने 68 दिनों तक इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा। फर्नीचर हटाने, घर की रंगाई–पुताई करने और घर को पुराने मालिक को सौंपने के बाद ही केस सीबीआई को सौंपा गया। इससे साफ है कि उद्धव ठाकरे सरकार सबूत मिटाना चाहती थी और यही वजह है कि सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। भाजपा विधायक ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की फिर से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की फिर से ˆप्ज जांच करेगी। यही मांग मैंने विधानसभा में रखी थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले में 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल कर दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं और अब अदालत को तय करना है कि वह (मामले को बंद करने की) रिपोर्ट को स्वीकार करती है या आगे जांच के निर्देश देती है। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में 14 जून, 2020 को फंदे से लटके हुए पाए गए थे। वह 34 साल के थे। केंद्रीय एजेंसी ने बिहार पुलिस से मामले की जांच संभाली थी। बिहार पुलिस ने सुशांत के पिता के.के. सिंह द्वारा पटना में दाखिल शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सीबीआई को दिये गये चिकित्सा विधिक परामर्श में "जहर देने और गला घोंटने" को लेकर इस मामले में किये गये दावों को खारिज कर दिया था।

राम नवमी पर रामेश्वरम में रहेंगे पीएम मोदी, पूजा-अर्चना के बाद करेंगे पंबन ब्रिज का उद्घाटन

नई दिल्ली, एजेंसी। 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा–अर्चना करेंगे और नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। मोदी रामनवमी पर तमिलनाडु में नए पंबन पुल का उद्घाटन कर सकते हैं, जिससे रामेश्वरम तक रेल संपर्क में सुधार होगा – जो सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि रामेश्वरम वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने रावण को हराने के लिए लंका तक जाने के लिए पुल का निर्माण किया था, जैसा कि रामायण में वर्णित है। रामेश्वरम मंदिर में हर साल 25 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं और उम्मीद है कि उन्नत बुनियादी ढाँचे से पर्यटन और तीर्थयात्रा को बढ़ावा मिलेगा। जहां तक घ्प्रतीकात्मकता की बात है, प्रधानमंत्री द्वारा रामनवमी के दिन पुल का उद्घाटन किए जाने की संभावना का महत्व काफी बड़ा है, जिस दिन हिंदुओं का मानना घ्है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है, वह है संभावित उद्घाटन का समय–जब तमिलनाडु में डीएमके सरकार भाषा के मुद्दे और अभी तक घोषित नहीं किए गए परिसीमन को लेकर केंद्र के खिलाफ युद्ध की राह पर चल रही है। नए पुल, देश का पहला ऊर्ध्वाधर समुद्री पुल, यात्रियों के लिए अधिक आराम सुनिश्चित करने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि समुद्री पुल के व्यावसायिक उद्घाटन की तैयारी जोरों पर है और पिछले कुछ दिनों में दक्षिण रेलवे के शीर्ष रेलवे अधिकारी पुल और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्घाटन प्रधानमंत्री के श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा (4 और 5 अप्रैल) से लौटने के तुरंत बाद होने की संभावना है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं और उन्हें नियंत्रण और संतुलन के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह टिप्पणी राज्यसभा में एक दिन पहले की गई टिप्पणी के बाद किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ष्चीजें अलग होतींष यदि न्यायिक नियुक्तियों के लिए तंत्र – राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का संदर्भ देते हुए – को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया होता। उन्होंने, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित घर पर नोटों की गड्डियां मिलने पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए कल मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की शाम साढ़े चार बजे एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा, मुझे सदन को यह बताना होगा कि कल हमने उस मुद्दे पर बहुत ही सार्थक बातचीत की, जो जनता के मन में हलचल मचा रहा है। कल संपन्न हुई इस बैठक में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। सभापति ने बैठक का विस्तृत ब्यौरा न देते हुए कहा कि विचार–विमर्श आम सहमति से हुआ, जिससे सहयोग और चिंता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा संस्थाओं के बीच का नहीं है। उन्होंने कहा '' ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका एक–दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं।'' धनखड़ ने कहा, ''देश में सभी संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा... और साथ ही, निगरानी और संतुलन भी होना चाहिए, जिसका उद्देश्य अच्छा है।''

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर हाल में कथित तौर पर अवैध नकदी मिलने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर की गयी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष यह याचिका बुधवार को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गयी। मुख्य याचिकाकर्ता अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने सीजेआई के समक्ष मामले का उल्लेख किया।न्यायमूर्ति खन्ना ने शुरू में टिप्पणी की, "आपका मामला सूचीबद्ध हो गया है। कोई सार्वजनिक बयान न दें।" नेदुम्परा ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया और जले हुए नोटों के वीडियो सहित प्रासंगिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के लिए सीजेआई की सराहना की। सीजेआई ने याचिकाकर्ता को सुनवाई की तारीख के लिए रजिस्ट्री से जांच करने की सलाह दी। नेदुम्परा के साथ मौजूद एक अन्य सह–याचिकाकर्ता ने टिप्पणी की, "अगर यह रकम किसी व्यवसायी के घर पर पाई गई होती, तो ईडी और आयकर जैसी एजेंसियां घ्तुरंत कार्रवाई करतीं।"

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ सुविधाओं को लेकर भेदभाव, उनकी आवाज बुलंद करुंगा : राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को मिलने वाले सम्मान तथा सुविधाओं में "भेदभाव" पूरी तरह अस्वीकार्य है और वह उन्हें न्याय दिलाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त जवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राहुल गांधी से संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया, "संसद भवन में छह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त जवानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई।

मोदी सरकार में अरबपति बने खरबपति, गरीब हुए कंगाल : खरगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार में आर्थिक असमानता इतनी भयावह स्तर पर है कि अरबपति, खरबपति बन चुके हैं और गरीब, कंगाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के बीच सरकार ''सबका साथ, सबका विकास'' का ढिंढोरा पीटती फिर रही है।''

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''पिछले 78 वर्षों से किसी सरकार ने आम जनता को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर नहीं किया, जितना मोदी सरकार ने किया है। आर्थिक असामनता भयावह स्तर पर है। अरबपति, खरबपति बन चुके हैं, (और) गरीब, कंगाल हो रहे हैं। ब्रिटिश–राज के दौरान 1820 में मध्यम वर्ग की आमदनी की जो स्थिति थी, वही (स्थिति) आज हो गई है।'' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के आंकड़े बताते हैं कि भले ही वह कोई उन्नत डिग्री वाला व्यक्ति हो या कोई कुशल नौकरी कर रहा हो, फिर भी उसे दुनिया में सातवीं सबसे कम मजदूरी दी जाती है।

मजदूर के घर में लगी आग से जला बेटियों का दहेज

मोरना। जंगल मे मजदूरी करने गये मजदूर के घर मे अज्ञात कारणों से आग लग गयी। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया।आग लगने से कीमती सामान सहित घर मे रखा दो बेटियों के दहेज का सामान भी जलकर खराब हो गया पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। भोपा थाना क्षेत्र के गांव तिस्सा निवासी नूरमोहम्मद मलिक मजदूरी कर परिवार का भरण

पोषण करता है। बुधवार को परिवार के सदस्य जंगल मे मजदूरी करने गया था। घर मे दो छोटी बच्चियां मुस्कान व सकीना मौजूद थी तभी घर मे आग लग गयी।बालिकाओं ने शोर मचाया तो पड़ोसी उधर दौड़े और आग को शांत किया। तब तक घर मे रखा कीमती सामान जल कर खराब हो गया। नूर मोहम्मद ने बताया की घर मे आग लगने की सूचना पर घर पहुंचे तो सामान जल चुका था। नूर मोहम्मद के परिवार मे पत्नी मयराज के अलावा पुत्री रुखसार, रेशमा, शाहवेज नवेद, अनस, मुस्कान, सकीना हैं। रुखसार व रेशमा की शादी आगामी मई माह मे होनी है। शादी की तैयारियों के बीच घर मे दोनों बेटियों के दहेज का सामान रखा हुआ था जो आग मे जल गया है। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मौके पर पहुंची भोपा पुलिस ने बताया की बिजली के शॉट सर्किट के कारण आग लगी है।

त्रिदिवसीय प्रादेशिक रोवर/रेंजर समागम -2025 का शुभारम्भ

प्रयागराज। प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज में दिनाङ्क 26 से 28 मार्च तक आयोजित हो रहे त्रिदिवसीय प्रादेशिक रोवरध्रेंजर समागम का उद्घाटन कुलपति डॉ.अखिलेश कुमार सिंह ने किया। संस्कृत विभाग के छात्रों के वैदिक मंगलाचरण के पश्चात मुख्य अतिथि भारत स्काउट गाइड उ.प्र. के प्रादेशिक आयुक्त डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि ऐसे समारोह से विद्यार्थियों में रचनात्मक क्रिया कलाप का विस्तार होता है। कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि यह समागम देश सेवा, समर्पण भाव को जीवंत करता है। मंचस्थ अतिथियों में कुलानुशासक प्रो. राजकुमार गुप्त, अधिष्ठाता कला संकाय प्रो. विवेक कुमार सिंह, अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण प्रो. आशुतोष कुमार सिंह, वित्ताधिकारी शशि भूषण सिंह तोमर, परीक्षा

नियंत्रक डॉ. विनीता यादव, कुलसचिव संजय कुमार , कमलेश द्विवेदी एवं शिक्षकगण व विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। रज्जू विश्वविद्यालय की छात्राओं ने मोहक नृत्य का प्रदर्शन किया।इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय से आये रोवर रेंजर्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस समागम समारोह का समापन 28 मार्च को होगा।

फोर लेन मार्ग पर डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर, किसानों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का किया घेराव

मथुरा। भारतीय किसान यूनियन भानु के गुस्साए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेश ठैनुआ, जिलाध्यक्ष देवेन्द्र पहलवान,प्रदेश अध्यक्ष पहलवान प्रकोष्ठ भूरा पहलवान के नेतृत्व में कृष्णापुरी चौराहे पर स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय का

यमुना एक्सप्रेस-वे से वृंदावन को जोड़ने वाले फोर लेन मार्ग पर डिवाइडर और नाली निर्माण की मांग को लेकर कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। जिसके बाद किसान डिवाइडर बनाए जाने की मांग को लेकर अधिकारियों का घेराव कर कार्यालय के अंदर फर्श पर बैठ गए। जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेश ठैनुआ और जिलाध्यक्ष देवेन्द्र पहलवान ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर यमुना एक्सप्रेस-वे के फोर लेन मार्ग पर पानीगांव के पास डिवाइडर न बनाने और रिश्वत व दलाली लेकर काम करने का आरोप लगाते हुए लोक निर्माण विभाग कार्यालय मथुरा का करीब एक घंटे तक घेराव किया। जहां अधिशासी अभियन्ता गुलवीर सिंह को फोर लेन मार्ग पर डिवाइडर के निर्माण को लेकर अवगत कराया।

डा. प्रदीप चित्रांशी और डा. अजय मालवीय को मिला साहित्य वारिधि सम्मान

प्रयागराज। महानगर के साहित्यकारों और प्रकाशकों द्वारा संयुक्त रूप से आज एक अनूठे प्रकल्प को मूर्तरुप दिया गया द्य 'साहित्यकार सत्कार रू आपके द्वार' नामक इस प्रकल्प में प्रति माह वरिष्ठ साहित्यकारों को उनके आवास पर जाकर सम्मानित करने के

क्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ प्रदीप चित्रांशी जी एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ अजय मालवीय जी को साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज की ओर से 'साहित्य वारिधि सम्मान' प्रदान किया गया। सारस्वत सभागार लूकरगंज प्रयागराज में आयोजित समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध गीत कार डॉ वीरेंद्र कुमार तिवारी ने किया। साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज के व्यवस्थापक डॉ भगवान प्रसाद उपाध्याय के संचालन में इस आयोजन में काव्य पाठ भी हुआ जिसमें युवा गजलकार सुशांत जी द्वारा श्री गणेश किया द्य चर्चित गीतकार शंभूनाथ श्रीवास्तव ने वसंत ऋतु के वर्णन को श्रृंगाररस से पूर्णता प्रदान किया। साहित्यकार केशव प्रकाश सक्सेना और सुनील दानिश ने गजल के माध्यम से गोष्ठी का सम्मान बढ़ाया। साहित्य में नये प्रतिमान गढ़ते हुए कवि हरीश वर्मा ने अपनी कविता से वाहवाही लूटी। अपनी बाल कविता के साथ प्रदीप सिंह ने गोष्ठी को गौरवान्वित किया। डॉ राम लखन चौरसिया वागीश ने वागीश नवनीतम की रचनाओं का वाचन करके खूब तालियाँ बटोरी।

सेना से अनापत्ति लेने में ही बीते नौ साल, लाइट मेट्रो परियोजना कैसे होगी साकार

प्रयागराज। प्रयागराज में यातायात को सुगम बनाने के लिए लाइट मेट्रो संचालन की तैयारी फिलहाल सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। इसके तहत 44 किलोमीटर में मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण दो चरणों में किया जाना है। पहले चरण में बमरौली से झूंसी स्थित सिटी लेक फॉरेस्ट तक 23 किलोमीटर में 21 स्टेशन तैयार होने हैं।

संगम नगरी के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट-2016 नौ साल बाद भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है। स्थिति यह है कि सेना से अनापत्ति के इंतजार में अब तक डीपीआर फाइनल नहीं हो सका है, जबकि इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों की 35 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। सेना से अनापत्ति और स्थलीय निरीक्षण के लिए अधिकारियों की 18 मार्च को प्रस्तावित बैठक एकबार फिर स्थगित हो चुकी है, जबकि अगली बैठक की अभी तारीख तय नहीं हो सकी है।

प्रयागराज में यातायात को सुगम बनाने के लिए लाइट मेट्रो संचालन की तैयारी फिलहाल सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। इसके तहत 44 किलोमीटर में मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण दो चरणों में किया जाना है। पहले चरण में बमरौली से झूंसी स्थित सिटी लेक फॉरेस्ट तक 23 किलोमीटर में 21 स्टेशन तैयार होने हैं। दूसरे चरण में शांतिपुरम से छिवकी तक 21 किलोमीटर में 19 स्टेशन बनने हैं। 8125 करोड़ की यह परियोजना वर्षों बाद भी बैठकों तक ही सीमित है।

इसके लिए यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, कर्नल क्यू एचक्यू पूर्व यूपी एंड एमपी सब एरिया, रक्षा संपदा अधिकारी प्रयागराज और राइट्स लिमिटेड नई दिल्ली के ज्वाइंट जनरल मैनेजर की 18 मार्च को बैठक प्रस्तावित थी। इससे अधिकारियों को भी कार्य आगे बढ़ने की आस जगी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई। बैठक में खासतौर पर कॉरिडोर के भूमि संरेखण स्टेशन एवं डिपो के लिए भूमि चिह्नित की जानी थी और रक्षा विभाग से अनापत्ति ली जानी थी।

विदित हो कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष-2016 में शासनादेश जारी कर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के विशेषज्ञ उपक्रम राइट्स लिमिटेड को डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राइट्स लिमिटेड ने डीपीआर की कंसल्टेंसी फीस 3.85 करोड़ और इसके अतिरिक्त प्रति किमी की लंबाई पर 11 लाख रुपये प्रति किमी की दर से प्रस्ताव रखा था, जिस पर न्यूनतम लंबाई हेतु 3.50 करोड़ और दस लाख प्रति किमी पर सहमति बनी। इसके अलावा नोडल एजेंसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लिए भी दस लाख रुपये प्रति किमी की दर से कंसल्टेंसी फीस तय किया गया। उस दौरान सचिव वंदना त्रिपाठी और नगर नियोजक आरके सिंह थे। स्थिति यह है कि अब तक पूर्ण रूप से डीपीआर फाइनल नहीं हो सका हैं।

आयुक्त की अध्यक्षता में लिया गया था निर्णय

आठ सितंबर 2016 को तत्कालीन आयुक्त राजन शुक्ला की अध्यक्षता में आयुक्त शिविर कार्यालय में बैठक हुई थी, जिसमें मेट्रो परियोजना के संचालन के लिए फिजिविलिटी स्टडी (डीपीआर) के संबंध में निर्णय लिया गया। इसमें ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के रूप में बमरौली एयरपोर्ट से त्रिवेणी पुरम कालोनी झूंसी तक और नार्थ-साउथ कॉरिडोर के रूप में शांतिपुरम कालोनी फाफामऊ से अलोपीबाग होते हुए नैनी तक प्रथम चरण का चयन किया गया। दोनों कॉरिडोर के लिए 40 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

राइट्स लिमिटेड से डीपीआर के लिए हुआ है अनुबंध रू नवनीत

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता नवनीत कुमार शर्मा का कहना है कि भारत सरकार के विशेषज्ञ उपक्रम मेसर्स राइट्स लिमिटेड से डीपीआर के लिए अनुबंध हुआ है। इसके लिए लखनऊ मेट्रो कारपोरेशन को समन्वयक और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को नोडल बनाया गया है। डीपीआर में अभी कुछ संशोधन होना है, इसके लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें डीपीआर पर अंतिम मुहर लगने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।

मेट्रो कॉरिडोर संरेखण एवं डिपो मैप स्टेशन तथा डिपो निर्माण के लिए चिन्हित भूमि को लेकर रक्षा विभाग से अपेक्षित सहमति के लिए 18 मार्च को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कतिपय कारणों से यह टल गई है। जल्द ही बैठक कर रक्षा विभाग से अपेक्षित सहमति मिलने के बाद संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और परियोजना को जल्द साकार करने का प्रयास किया जाएगा। - डा. अमित पाल शर्मा, उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के बीच मारपीट, दोनों घायल

प्रयागराज। छुट्टी के विवाद को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एसके शर्मा और उनके ही विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुमार पराग के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों शिक्षक घायल हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया। मामले में दोनों तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आंतरिक कमेटी गठित की है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के अंग्रेजी विभाग में मंगलवार को एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुमार पराग और विभागाध्यक्ष प्रो. एसके शर्मा के बीच मारपीट हुई। घटना में घायल हुए दोनों शिक्षकों को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। इविवि प्रशासन ने मामले में आंतरिक जांच कराने का निर्णय लिया है। वहीं, दोनों पक्षों एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए कर्नलगंज थाने में तहरीर दी है। विभागाध्यक्ष व कार्य परिषद के सदस्य प्रो. सुशील कुमार शर्मा ने तहरीर में आरोप लगाया कि उन्होंने विभागीय कार्य व कुछ जानकारी के लिए डॉ. पराग को फोन करके बुलाया था। दोपहर 12 बजे वह कमरा नंबर-16 में पहुंचे। उनसे कुछ जानकारी मांगी तो वह अचानक उग्र हो गए और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप लगाया कि लोहे की रॉड से हमला किया। रोकने का प्रयास करने पर हाथ, सिर व सीने पर गंभीर चोटें आईं। जमीन पर गिराकर लात-घूसों से मारा। सोने की चेन और रुद्राक्ष की माला छीन ली। इसके बाद प्रो. शर्मा बेहोश होकर गिर पड़े और आंख खुली तो खुद को बेली अस्पताल में पाया। उनके पास विभाग के ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विवेक द्विवेदी व कुछ अन्य लोग खड़े थे। प्राथमिक उपचार के बाद स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह देकर घर भेज दिया।

डॉ. पराग ने लगाया उंगली तोड़ने का आरोप

वहीं, ऑटा की नई कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. कुमार पराग ने बताया कि वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गोपनीय कार्य के लिए चार दिन की छुट्टी लेकर उत्तराखंड गए थे। तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी छुट्टी के आवेदन पर बात करने के लिए विभागाध्यक्ष प्रो. सुशील कुमार शर्मा ने उन्हें अपने चैंबर में बुलाया और असहमत होने पर अपशब्द कहने लगे। विरोध करने पर हाथ पकड़कर ऐंठने लगे और उंगली तोड़ दी।

शर्ट फाड़ दी व हत्या के इरादे से गर्दन दबाने लगे। उन्हें धक्का देकर डॉ. पराग किसी तरह चौंबर से बाहर निकले। डॉ. पराग के अनुसार, घटना के बाद सीधे इविवि के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचे और इसके बाद बेली अस्पताल गए। आरोप है कि वहां प्रो. सुशील के उकसाने पर डॉ. विवेक कुमार द्विवेदी व डॉ. मृत्युंजय राव परमार ने आधा दर्जन लोगों ने लाठी-डंडे व रॉड से उन पर हमला कर दिया। अस्पताल का पर्चा भी फाड़ दिया। 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस के पहुंचने के बाद उन्होंने एक निजी अस्पताल में इलाज कराया। उनकी उंगली में फ्रेक्चर है और घुटने व कोहनी में भी चोट आई है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में आंतरिक जांच कराई जाएगी। जांच के बाद विस्तृत जानकारी होने पर ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। - प्रो. जया कपूर, पीआरओ, इविवि

इविवि प्रशासन के प्रतिनिधियों से बात की गई है। आंतरिक जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। - प्रदीप कुमार सिंह, थाना प्रभारी, कर्नलगंज

अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मृत्युंजय राव परमार का कहना है कि इविवि में हुई घटना के बाद दोनों ही शिक्षकों को उन्होंने और कुछ अन्य शिक्षकों व छात्रों ने बेली अस्पताल पहुंचाया। डॉ. पराग के साथ अस्पताल में कोई मारपीट नहीं की गई। आरोप बेबुनियाद है।

पुलिस को इविवि की जांच रिपोर्ट का इंतजार

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में विभागाध्यक्ष व एसोसिएट प्रोफेसर के बीच मंगलवार को मारपीट हो गई थी। विभागाध्यक्ष प्रो. एसके शर्मा और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुमार पराग ने अस्पताल में इलाज कराने के बाद कर्नलगंज थाने में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी है। इविवि में शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना को लेकर बुधवार को भी दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इधर, पुलिस ने जब तहरीर के आधार पर इविवि प्रशासन से संपर्क किया, तो आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करने का बात कही गई है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इविवि प्रशासन की ओर स्वयं मामले की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। इसके बाद पुलिस जांच रिपोर्ट व दोनों पक्ष की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

डॉ. विजयानन्द गुजरात में हुए सम्मानित

प्रयागराज। हिंदी के सुपरिचित साहित्यकार डॉ०विजयानन्द को उनकी दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय,आनंद,गुजरात के सभागार में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम गुजरात साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो०निरंजन भाई पटेल ने की तथा मुख्य अतिथि स्वयं

विजयानन्द ही थे। संयोजन हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार मेहरा तथा अंकुर जी ने किया। इस अवसर पर डॉ विजयानन्द ने ७ साहित्य और रेडियो के अंतर्संबंध ७ पर व्याख्यान भी दिया। ज्ञात हो कि अभी उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का एक लाख रुपए का अखिल भारतीय कविता पुरस्कार तथा हिंदुस्तानी एकेडेमी प्रयागराज का दो लाख रुपए का भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 2019 में प्राप्त हो चुका है। वैश्विक हिंदी महासभा, अखिल भारतीय हिंदी परिषद, भारत के लगभग सभी प्रांतों के पदाधिकारियों तथा प्रयागराज के बुद्धिजीवियों ने उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दी है। डॉ० विजयानन्द जी विभिन्न संस्थाओं में सचिव,महामंत्री,निदेशक- रिसर्च फाउंडेशन,सं.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तविश्वविद्यालय,नई दिल्ली,का०अध्यक्ष- अखिल भारतीय साहित्य परिषद, प्रयागराज,अध्यक्ष -काशी प्रांत,राष्ट्रीय अध्यक्ष-विश्व हिंदी महासभा, नई दिल्ली जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं तथा हिन्दी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में 54 मौलिक, अनुदित,संपादित कुल 85 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने ३ वैश्विक साहित्य ३ त्रैमासिक का लगभग १० वर्षों तक लगातार संपादन किया है। अमेरिका के रामकाव्य पीयूष, कृष्णकाव्य पीयूष सहित, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,जापान सिंगापुर, मारीशस , मलेशिया, फिजी आदि अनेक देशों के काव्य संग्रहों,पत्र-पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। भारत के कई विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर एम०फिल, पीएचडी का शोध कार्य हो चुकाध चल रहा है।वे अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट के दो बार सलाहकार रहे।भारत सरकार,उत्तर प्रदेश सरकार सहित, देश-विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय ३ हरिऔध ३ पुरस्कार (मऊ,आजमगढ़), शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार (इलाहाबाद), सूचना प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार का सम्मान,मोहन राकेश नाटक पुरस्कार ,बाल साहित्य सम्मान (उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ), हिंदी अकादमी,मुंबई का शिक्षारत्न सम्मान, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, अखिल भारतीय हिंदी महासभा, कर्नाटक , विश्व हिंदी महासभा, , राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, विधानसभा, लखनऊ का पराग पुरस्कार, सयुक्तराष्ट्र विश्वविद्यालय, जापान, नेपाल सरकार आदि सहित कई दर्जन सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सन् 2001 में अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने इन्हें अपने रिसर्च बोर्ड का सलाहकार बनाया था।जिस पद पर रहकर इन्होंने कई वर्षों तक सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान में वे वैश्विक हिंदी महासभा के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

सेवानिवृत प्रधानाध्यापकों का हुआ विदाई समारोह

मथुरा। महावन तहसील के परिषदीय स्कूलों से 31 मार्च को सेवानिवृत हो रहे दो शिक्षकों का भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया।महावन तहसील में स्थित विकास खंड बलदेव के न्याय पंचायत हथकौली के प्राथमिक विद्यालय नगला पतिराम के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गौतम व न्याय पंचायत पटलौनी के प्राथमिक विद्यालय नगला मोहन के प्रधानाध्यापक तेजवीर सिंह के सेवानिवृत होने पर उनका विदाई समारोह कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर एवं माला पटुका पहनाकर सम्मानित किए गए। इस अवसर पर एकेडमिक रिसॉर्स पर्सन डा.जगदीश पाठक व कृष्ण

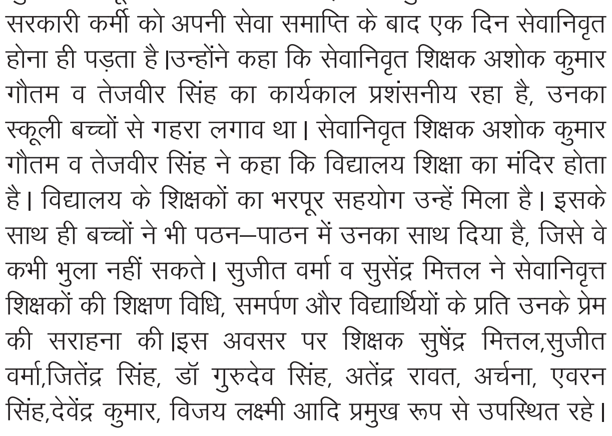

कुमार राजपूत ने कहा कि विदाई शब्द दुःखदायी होता है हर सरकारी कर्मी को अपनी सेवा समाप्ति के बाद एक दिन सेवानिवृत होना ही पड़ता है।उन्होंने कहा कि सेवानिवृत शिक्षक अशोक कुमार गौतम व तेजवीर सिंह का कार्यकाल प्रशंसनीय रहा है, उनका स्कूली बच्चों से गहरा लगाव था। सेवानिवृत शिक्षक अशोक कुमार गौतम व तेजवीर सिंह ने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। विद्यालय के शिक्षकों का भरपूर सहयोग उन्हें मिला है। इसके साथ ही बच्चों ने भी पठन-पाठन में उनका साथ दिया है, जिसे वे कभी भुला नहीं सकते। सुजीत वर्मा व सुसेंद्र मित्तल ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की शिक्षण विधि, समर्पण और विद्यार्थियों के प्रति उनके प्रेम की सराहना की।इस अवसर पर शिक्षक सुषेंद्र मित्तल,सुजीत वर्मा,जितेंद्र सिंह, डॉ गुरुदेव सिंह, अतेंद्र रावत, अर्चना, एवरन सिंह,देवेंद्र कुमार, विजय लक्ष्मी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित

प्रयागराज स स्व नर्वदेश्वर तिवारी जी की स्मृति में साहित्य घराना के तरफ से नवीन शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बेगम सराय मुंडेरा में कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजक श्रीराम तिवारी सहज द्वारा अपनी

पिता की स्मृति में कवियों को स्व नर्वदेश्वर तिवारी साहित्य सम्मान से नवाजा गयास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बसंत कुमार शर्मा विशिष्ट अतिथि श्रीमती अंजू विश्वकर्मा अवि एवं मनोज कुमार शर्मा को स्मृति चिन्ह दे कर संयोजक रामबीर सिंह पथिक द्वारा सम्मानित किया गया। अध्यक्षता कर रहे केशव सक्सेना के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों ने अलग अलग रसों में काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर लिया। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों में अनिल सिंह सुमन सविता श्रीवास्तव पुष्पांजलि जोशी संध्या मिश्रा उपेन्द्र पांडे हृदयनारायण पांडे ईश्वर चंद्र शुक्ल एवं अन्य उपस्थित रहे।

देश की खुशहाली के लिए संदीप भगत ने की कठिन तपस्या

मोरना। देश मे सुख–समृद्धि और खुशहाली के लिए संदीप भगत द्वारा 21 दिन की कठिन तपस्या की गयी। तपस्या पूर्ण होने पर हवन यज्ञ किया गया तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें साधु संतो सहित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ककरोली क्षेत्र के गांव दरियाबाद में बुधवार को संदीप भगत जी 21 दिन की तपस्या पूर्ण होने पर कृपाल दास महाराज द्वारा विधि–विधान से हवन–यज्ञ संपन्न कराया गया। इसके पश्चात संदीप भगत को विधिवत रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनेक साधु–संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भजन–कीर्तन के बीच वेद मंत्रों का जाप हुआ। उपस्थित संतों को दक्षिणा व प्रसाद अर्पित किया गया।संदीप भगत जी ने कहा कि उनकी तपस्या देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए है। पूर्व मे भी वह कठिन तपस्या कर प्रभु भक्ति मे ध्यान लगा चुके हैं।इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन उपस्थित रहे। आयोजन स्थल पर भक्तिमय माहौल बना रहा और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।इस दौरान सच्चा प्रकाश आश्रम की संचालिका साध्वी पूजा, पंडितरामू मिश्रा,ओमनाथ महाराज, धुनी नाथ,अमरदास महाराज , पप्पू नाथ, छोटू,सुधीर कुमार,शिवांक ,विकास, महक पाल प्रधान,डॉक्टर टीटू,अनमोल, आदित्य,आदि उपस्थित रहे।

एकल अभियान तेजपुर अंचल के सौजन्य में पांच दिवसीय आवासीय आचार्य – आचार्या अभ्यास वर्ग संपन्न

विश्वनाथ, असम। राज्य के विश्वनाथ जिले पाभोई रोड के खेरबाड़ी प्राथमिक विद्यालय में कल एकल अभियान तेजपुर अंचल के अंतर्गत चाराली तथा पाभोई संच के आचार्य – आचार्या का पांच दिवसीय आवासीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। चाराली संच के विशेष सहयोग से आयोजित पाँच दिवसीय अभ्यास वर्ग के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र का शुभारंभ भारत माता, ॐ और सरस्वती माँ के समीप दीप प्रज्ज्वलित और मंत्रोच्चार से हुआ। जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्वनाथ नगर कार्यवाह अपूर्व कुमार दास ,चाराली संच अध्यक्ष बिराज कुर्मी, भाजपा विश्वनाथ जिला साधारण सचिव रातुल नाथ , कल्याण आश्रम असम विश्वनाथ जिला के सांगठनिक मंत्री सोमराम भगत , कल्याण आश्रम असम के विश्वनाथ जिला अंशकालिक कार्यकर्ता संतोष कुमार महतो ,खोरबारी प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तुलसी शाह के उपस्थित में किया गया। इस आवासीय अभ्यास वर्ग में बौद्धिक, सत्र तथा प्रशिक्षक के रूप में क्रमशः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्वनाथ जिला मुख्य मार्ग प्रमुख डा० सरजीत दास , राष्ट्रीय सेविका संघ विभाग संपर्क प्रमुख शांता बरठाकुर, उत्तर असम प्रांत के धर्मजागरण प्रमुख योगेश शास्त्री , प्रचारक कार्तिक गढ़, विश्वनाथ जिला बौद्धिक प्रमुख दीपांकर देवनाथ ,समाजिक कार्यकर्ता मृदुल हाजरिका , तेजपुर अंचल अभिनय प्रमुख फिरोज दलै, चारिआलि संच के प्रमुख मिथिला मुंडा , तेजपुर अंचल प्राथमिक शिक्षा प्रमुख कुष्मा लोहार , पाभोई संच के सदस्य अनिल तांति आदि ने अपने व्याख्यान से प्रभावित किया। मंगलवार के समापन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह राणा तसा, पश्चिम पूर्वोत्तर संभाग के सुमित मुड़ा,पाभोई संच प्रमुख पुण्य दास आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।इस कार्य को संपन्न करने के लिए स्वागत समिति बनाए गए जिसमें अध्यक्ष रबिन भूमिज , सचिव हनसिंग रंग्पी और सदस्य गोपाल कुमार शाह , जयंत रंग्पी , तुलसी शाह , अमित सहर ,रामू चावासी , सदस्या आरती भूमिज के देखरेख में अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ।

लोकसभा आश्वासन समिति सभापति बनने पर सांसद हरेंद्र सिंह मलिक का जोरदार स्वागत

जिलाध्यक्ष जिया चौधरी राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा द्वारा आयोजित सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जताया आभार

मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने जानकारी देते हुए बताया की समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयासों से मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक को लोकसभा की आश्वासन समिति का सभापति बनाए जाने पर सपा कार्यालय पर आयोजित विशाल सभा में उनका स्वागत व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया गया।

आभार सभा में पहुंचे हजारों कार्यकर्ता तथा क्षेत्रीय लोगों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव व मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि आज जो भी सम्मान मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद के रूप में मिल रहा है वह क्षेत्रीय जनता कि हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मान है।उन्होंने कहा की क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को लेकर चुप नहीं रहेंगे तथा सड़क हो या संसद उनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्षेत्रीय जनता के काम तथा सम्मान है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न व अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगातार सम्मान देने पर उनका आभार जताया तथा समाजवादी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया।

सभा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताते हुए कहा कि उनके द्वारा मुजफ्फरनगर की जनता को सम्मान देने के रूप में

समाजवादी पार्टी सांसद व समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक को दिया जा रहा सम्मान कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता व सक्रियता को बढ़ाने का काम करेगा उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए सक्रिय रहेगा उसके सम्मान के लिए एकजुट होकर काम किया जाएगा।समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा ने भारी संख्या में आए लोगों का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा की विनाशकारी राजनीति से जनता परेशान हो गई है। भाजपा की सरकार में किसान मजदूर नौजवान तथा महिलाओं की सुविधा के लिए कोई बात नहीं की जाकर उनको नफरत का एजेंडा चलाकर वास्तविक मुद्दों को दबाया जा रहा है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है उन्होंने सांसद हरेंद्र मलिक को लोकसभा आश्वासन समिति सभापति के रूप में सम्मान दिए जाने पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया।

सभा का संचालन समाजवादी पार्टी जिला महासचिव चौधरी विकिल गोल्डी अहलावत द्वारा किया गया।सभा को मुख्य रूप से पूर्व मंत्री राजकुमार यादव पूर्व मंत्री महेश बंसल समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव नौशाद अहमद प्रदेश सचिव विनय पाल सिंह पाल पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हाथरस जसवीर वाल्मीकि जिला उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह कोरी, शमशेर मलिक जिला पंचायत सदस्य व जिला उपाध्यक्ष अमीर कासिम एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह नीटू,चौधरी ओमपाल सिंह पूर्व चेयरमैन अमलेश शर्मा जिला कोषाध्यक्ष सैयद अली अब्बास काजमी समाजवादी अल्पसंख्यक सभा प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार देवेंद्र सिंह खालसा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तहसीन मंसूरी धनवीर कश्यप समाजवादी पार्टी जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन विधानसभा अध्यक्ष डॉ अविनाश कपिल सादिक चौहान सत्यदेव शर्मा अकरम खान सत्यवीर त्यागी इमरोज पायलट चौधरी यशपाल सिंह चौधरी अजय कुमार रमेश चंद शर्मा ठाकुर राजेंद्र सिंह सपा नेता सत्येंद्र पाल,रोहित चौधरी सर्वेंद्र राठी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सतीश गुर्जर समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष उमेश त्यागी मुलायम सिंह यादव यूथ बिग्रेड जिला अध्यक्ष राशिद मलिक समाजवादी लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष टीटू पाल रमन समाजवादी मजदूर सभा जिला अध्यक्ष नासिर राणा राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवजन सभा सचिन पाल सरदार प्रेम सिंह ऐश मोहम्मद मेवाती डॉ अली शेर अंसारी हाजी इमरान सिद्दीकी इकबाल अहमद इमलाक प्रधान नेपाल सिंह एडवोकेट तरुण सौदे एडवोकेट अली जामिन जैदी सभासद शहजाद चीकू हसीब राणा सुंदर सिंह सलीम राणा सुमित पवार बारी रिशु शर्मा एडवोकेट श्याम सुंदर आदि ने संबोधित किया।

चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने 11.40 लाख से तैयार कराया गौशाला मार्ग द्वार, मंत्री कपिल देव ने किया लोकार्पण

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् के द्वारा कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार होकर दयनीय स्थिति में पड़े शहर के मौहल्ला गौशाला मार्ग के मुख्य द्वार का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही इसे विकास की एक सौगात के रूप में जनता को समर्पित करने का काम किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने फीता काटकर गौशाला मार्ग द्वार का लोकार्पण कर मौहल्ले के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूर्ण कराने का काम किया गया। इसके चलते लोगों ने यहां आतिशबाजी कर हर्ष व्यक्त किया।

शहर के शामली रोड स्थित मौहल्ला गौशाला के काली नदी रोड मुख्य मार्ग पर बरसों पहले लोगों ने आपसी चंदा कर एक गेट बनाने का काम किया था, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक उठा–पटक शुरू हो जाने के कारण यह मुख्य द्वार उपेक्षा का शिकार हो गया और इसका निर्माण कार्य भी रुक गया था। इसके बाद लगातार क्षेत्र के लोग इस द्वार का निर्माण कार्य कराये जाने के लिए संघर्ष करते रहे। पिछले दिनों नगरपालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप से भी सभासद के साथ लोगों ने भेंटकर इस मुख्य द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग की थी। उन्होंने भरोसा ही नहीं दिया, बल्कि विशेष प्रयासों के कारण इसको पूरा करने का काम भी कर दिखाया।

मंगलवार की रात गौशाला मार्ग के मुख्य द्वार को पालिका की ओर से जनता को समर्पित कर दिया गया। यहां जश्न जैसे माहौल के बीच मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के द्वारा फीता काटा और नारियल फोड़कर इस मुख्य द्वार का लोकार्पण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने दोनों अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। मिठाई भी बांटी गई और बरसों की मुराद पूरी होने के कारण क्षेत्र के लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया तो पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप और मंत्री कपिल देव का आभार भी प्रकट किया। मंत्री कपिल देव ने बताया कि गौशाला नदी रोड मौहल्ले के मुख्य मार्ग पर लोगों के द्वारा गौशाला को समर्पित एक द्वार का निर्माण कार्य बरसों पहले शुरू किया गया था, लेकिन सपा शासन काल में धार्मिक जुलूस निकालने के लिए विवाद उत्पन्न होने के बाद इस द्वार का निर्माण कार्य रुकवाकर इसका कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था, इसके बाद से लगातार क्षेत्र के लोग इसके पुनः निर्माण की मांग करते आ रहे थे। इस बहुप्रतिक्षित मुख्य द्वार का निर्माण नगरपालिका परिषद् की ओर से कराया गया है, जनता में हर्ष है।

पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 28 के अन्तर्गत मौहल्ला गौशाला के मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त द्वार के निर्माण का कार्य पालिका द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराया गया है। इसका निर्माण दो चरणों में पूरा हुआ है। इस पर कुल 11.40 लाख रुपये का बजट खर्च किया गया है। पहले चरण में इसका मुख्य ढांचा तैयार किया गया, जिस पर 5.18 लाख रुपये खर्च हुए और दूसरे चरण में गेट के मुख्य ढांचा पर पत्थर लगवाने के साथ ही इसके शिखर पर भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर स्थापित कराया गया है, जिस पर 6.22 लाख रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने इसे जनता के लिए पालिका की सौगात बताते हुए कहा कि शहर के विकास की यह रफ्तार रुकने नहीं दी जायेगी। इस अवसर वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव स्वरूप, सभासद राजीव शर्मा, मनोज वर्मा, योगेश मित्तल, मोहित मलिक, विजय कुमार चिंटू, प्रशांत कुमार, भाजपा नेता संजय गर्ग, सुनील तायल, श्रीमोहन तायल, जगदीश पांचाल, राधे वर्मा, मनुप्रिय मजदूर, अमित वाल्मीकि, अलका शर्मा, आशुतोष गुप्ता व गणमान्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

आरेडिका में महाप्रबंधक ने किया चिल्ड्रेन फुटबॉल ग्राउण्ड का उद्घाटन

रायबरेली। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में महाप्रबंधक प्रशान्त कुमार मिश्रा तथा आरेडिका महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा भारती मिश्रा ने टाइप–2 एवं टाइप–3 कॉलोनी के मध्य स्थित 161 • 62 मी0 के चिल्ड्रेन फुटबाल ग्राउण्ड का उद्घाटन आरेडिका के उच्च अधिकारियों एवं कॉलोनीवासियों के साथ किया। महाप्रबंधक एवं उच्चाधिकारियों ने खिलाड़ी बच्चों के साथ बातचीत की एवं फुटबॉल खेल कर बच्चों का उत्साह वर्धन किया। महाप्रबंधक ने बच्चों से वार्तालाप के दौरान कहा कि यह फुटबाल ग्राउण्ड आपके लिए बनाया है आप लोग इस का उपयोग कीजिए। इससे आपके मन में खेल भावना का विकास होगा तथा यह मैदान खेलों के प्रति रुचि पैदा कर शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ्य बनाने में मदद करेगा। इस ग्राउण्ड का उपयोग कॉलोनी के लोग सुबह टहलने एवं सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। पार्क को हरा–भरा बनाने के लिए अशोक, बरगद, आदि के लगभग 151 पौधों का रोपण कार्य भी किया गया। पार्क में हरियाली के विकास हेतु जलप्रबंधन की उचित व्यवस्था की गई है। महाप्रबंधक महोदय ने सिविल इंजीनीरिंग विभाग को इस कार्य हेतु नगद पुरस्कार प्रदान करने के लिए आदेशित किया। इस अवसर पर आरेडिका सिविल इंजीनीरिंग विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता एसपी यादव, खेलकूद संघ के अध्यक्ष तथा प्रधान वित सलाहकार बीएल मीना, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता विवेक खरे, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक राजीव खण्डेलवाल, प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता मनोज कुमार जिंदल, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रमेश चन्द्रा, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव, आरेडिका महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं, कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि सहित उच्चाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

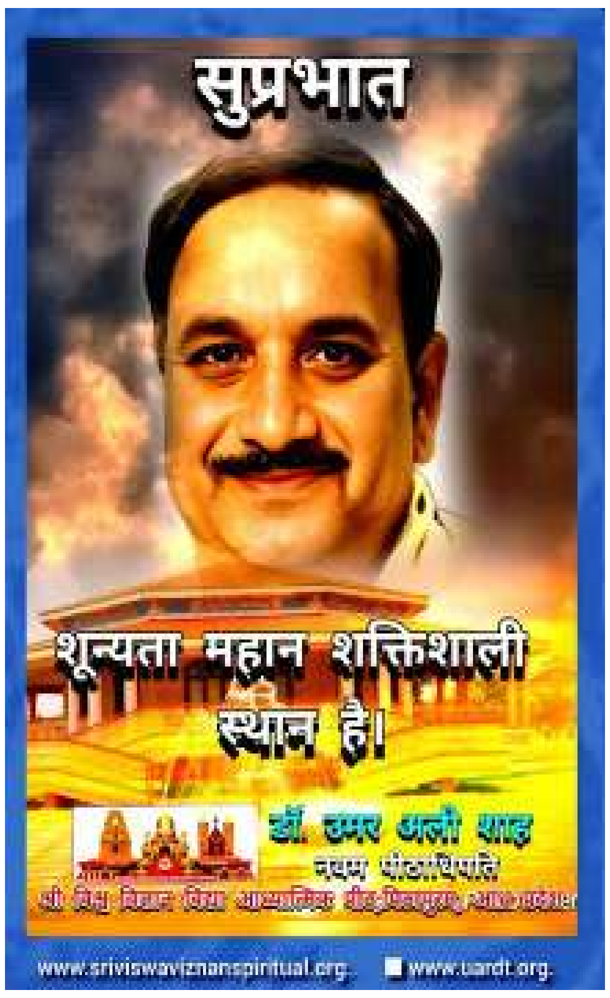

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 20176/20175 आगरा कैण्ट-बनारस वन्दे भारत रेलगाड़ी के संचालन दिन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

गाड़ी संख्या 20176/20175 आगरा कैण्ट-बनारस वन्दे भारत रेलगाड़ी के संचालन दिन में परिवर्तन

गाड़ी संख्या एवं नाम	वर्तमान संचालन का दिन	परिवर्तित संचालन का दिन	तिथि से प्रभावी
20176/20175 आगरा कैण्ट-बनारस वन्दे भारत एक्सप्रेस	सप्ताह में 6 दिन (शुक्रवार छोड़कर)	सप्ताह में 6 दिन (बुधवार छोड़कर)	26.05.2025 आगरा कैण्ट एवं बनारस से

नोट : ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नं0 139 या Railmadad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 541/25 (C)

उत्तर मध्य रेलवे

(अन्तर्गत धारा 20एफ (4) रेलवे अधिनियम 1989 यथासंशोधित-2008)

सार्वजनिक नोटिस दिनांक : 05.03.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने रेलवे अधिनियम 2008 (2008 का 11वॉं) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत का राजपत्र, आसाधरण, भाग-11 खण्ड-2 उप-खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना संख्या 898(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या 3511 (अ) दिनांक 20 अगस्त, 2024 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागराज जिले के करछना तहसील में विशेष रेल परियोजना, अर्थात प्रयागराज पं0 दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 कि0मी0) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन-दैनिक समाचार पत्रों अर्थात अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 28 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया था और इस परियोजना में प्राप्त सभी आक्षेप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए है, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय सरकार को सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का राजपत्र (आसाधारण) के भाग-11 खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) में सं0 891 नई दिल्ली दिनांक 20.02.2025 को रेल मंत्रालय उ0म0रेलवे (निर्माण विभाग), की अधिसूचना संख्या का.आ. 898(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2025 से यह घोषणा कर दी गयी है तथा धारा 20ई की उक्त घोषणा को दैनिक पत्र हिन्दुस्तान के अंक दिनांक 27.02.2025 के पृष्ठ 11 में तथा दैनिक पत्र द टाइम्स आफ इण्डिया के अंक दिनांक 27.02.2025 के पृष्ठ संख्या 11 में सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित कराया गया है। अतएव उक्त अधिनियम की धारा 20च की उपधारा (4) में प्रतिकर धनराशि को अवधारित करने से पूर्व इस आशय की सार्वजनिक नोटिस दी जाती है कि अर्जित की जानी भूमि मे हितबद्ध सभी व्यक्तियों से इस आशय का दावा आमन्त्रित किया जाता है कि अधिग्रहित भूमि में अपने से संबंधित हित को प्रकृति तथा ऐसे हितों के संबंध में दावे की धनराशि यदि कोई हो तो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के भी दावे को साथ संलग्न करते हुए कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) कलेक्ट्रेट परिसर प्रयागराज में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से एक सप्ताह के अन्दर प्रदान किया जाता है।

(रमेश मौर्य)
सक्षम प्राधिकारी/विशेषभूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), प्रयागराज

533/25 (C)

@CPRONCR North central railways @cpronclry CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

उत्तर मध्य रेलवे

(अन्तर्गत धारा 20एफ (4) रेलवे अधिनियम 1989 यथासंशोधित-2008)

दिनांक-05/03/2025 सार्वजनिक नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने रेलवे अधिनियम 2008 (2008 का 11वॉं) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत का राजपत्र, आसाधरण, भाग- ।। खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना संख्या 899 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या 3510 (अ) दिनांक 20 अगस्त, 2024 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में विशेष रेल परियोजना, अर्थात प्रयागराज पं0 दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 कि0मी0) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 28 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया था और इस परियोजना में प्राप्त सभी आक्षेप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए है, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय सरकार को सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का राजपत्र (आसाधारण) के भाग-।। खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) में सं0 892 नई दिल्ली दिनांक 20.02.2025 को रेल मंत्रालय उ0म0रेलवे (निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 899 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2025 से यह घोषणा कर दी गयी है तथा धारा 20ई की उक्त घोषणा को दैनिक पत्र अमर उजाला के अंक दिनांक 01.03.2025 के पृष्ठ 9 में तथा दैनिक पत्र द टाइम्स आफ इण्डिया के अंक दिनांक 01.03.2025 के पृष्ठ संख्या 11 में सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित कराया गया है। अतएव उक्त अधिनियम की धारा 20च की उपधारा (4) में प्रतिकर धनराशि को अवधारित करने से पूर्व इस आशय की सार्वजनिक नोटिस दी जाती है कि अर्जित की जानी भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से इस आशय का दावा आमन्त्रित किया जाता है कि अधिग्रहित भूमि में अपने से संबंधित हित को प्रकृति तथा ऐसे हितों के संबंध में दावे की धनराशि यदि कोई हो तो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के भी दावे को साथ संलग्न करते हुए कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) कलेक्ट्रेट परिसर प्रयागराज में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से एक सप्ताह के अन्दर प्रदान किया जाता है।

(रमेश मौर्य)
सक्षम प्राधिकारी /
विशेषभूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), प्रयागराज ।

542/25 (D)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

सम्पादकीय........

नगदी और न्याय

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के एक स्टोररूम से कथित रूप से बेहिसाब नगदी की बरामदगी ने देश के जनमानस व न्यायिक बिरादरी को झकझोरा है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक जांच समिति गठित की है। वहीं पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गलत सूचनाओं को दूर करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की है। इस रिपोर्ट ने निष्कर्ष दिया है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। ऐसा जरूरी भी था क्योंकि उच्च न्यायपालिका की ईमानदारी और विश्वसनीयता दांव पर है। हालांकि, न्यायाधीश ने दावा किया है कि उनके या परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी कोई नकदी नहीं रखी गई थी। इस बयान ने भी कई सवालों को जन्म दिया है। सवाल उठाया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा में रहने वाले सरकारी आवास में क्या बिना जानकारी के पैसा रखा जा सकता है? तो क्या किन्हीं आवासीय कर्मचारियों या बाहरी लोगों ने ऐसा कृत्य किया? यदि यह वास्तव में जज को फंसाने की सजिश थी, तो उसमें कौन लोग शामिल थे? निश्चित रूप से ऐसे सवालों का जवाब मिलने में विलंब से अविश्वास की धुंध और गहरी होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए ऐतिहासिक– 'न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन' में यह निर्दिष्ट किया गया था कि किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए, जो उनके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के अनुरूप न हो।' निस्संदेह, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने वाले किसी भी विवाद की गहरी जांच होनी चाहिए। साथ यह भी जरूरी है कि जांच निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूरी हो। वास्तव में सत्य, न्याय और न्यायिक जवाबदेही के हित में ऐसे मामलों में कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने का दायित्व अदालतों और जांच एजेंसियों का है। बहरहाल,शीर्ष अदालत ने विवादों में घिरे न्यायाधीश के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में शीर्ष अदालत ने जिस तरह तत्परता से कार्रवाई की और पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कदम उठाए, उसे सराहा गया। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है। यहां तक कि अदालत ने पिछले छह माह के कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक विमर्श में ला दी है। निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से बेदाग होने की उम्मीद की जाती है। सोशल मीडिया पर इस प्रकरण से जुड़ी सामग्री के वायरल होने के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, ताकि सच सामने आ सके। यदि कोई साजिश है तो उसका खुलासा हो और यदि नहीं तो न्यायिक व्यवस्था की शुचिता अक्षुण बनाये रखने के लिये सख्त कार्रवाई की जाए। यह एक हकीकत है कि अन्याय के विरुद्ध उम्मीद की अंतिम किरण लेकर व्यक्ति न्याय की चौखट पर दस्तक देता है। यदि ऐसे प्रकरण सच साबित होते हैं तो उसके विश्वास को धक्का लगेगा। निस्संदेह, न्याय व्यवस्था का सवालों के घेरे में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर छींटे आए हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। आम लोगों को विश्वास है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता बनाये रखने के लिये यह बेहद जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करना भी है। कमोबेश यहां न्यायिक अस्मिता को अक्षुण्ण बनाये रखना भी अनिवार्य शर्त है। अन्यथा न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर आंच आ सकती है।

कटाक्षों से घबराती सरकार

डॉ. दीपक पाचपोर

पार्टी प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि कुणाल को महाराष्ट्र ही नहीं हिन्दुस्तान भर में कहीं भी घूमने–फिरने नहीं दिया जायेगा। ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के का कहना है कि कामरा एक अनुबंधित कॉमेडियन हैं। मगर उन्हें सांप की पूंछ पर पैर नहीं रखना चाहिए था।

सत्ता जब अनैतिक तरीके से पायी और चलायी जाये तो उससे उपजा अपराध भाव सियासतदानों को एक हास्य कलाकार से भी डरा देता है। फिर उसकी आवाज दबाने के लिये कानून की बजाय राज्य अपनी मशीनरी तथा संगठन की ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है रविवार को मुंबई के खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में, जहां प्रसिद्ध हास्य कलाकार कुणाल कामरा का शो हुआ था जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनीति पर करारे व्यंग्य कसे थे और किसी का भी नाम लिए बिना नेताओं की अवसरवादिता पर कटाक्ष किया था। इससे नाराज शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल में जमकर तोड़–फोड़ की, साथ ही कामरा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और उन्हें देश भर में कहीं भी न घूमने–फिरने की चेतावनी दी जा रही है। कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) और 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वैसे कुणाल के जिस मजाक पर शिंदे गुट के शिवसैनिक नाराज हैं व एफआईआर दर्ज है उसमें न तो उप मुख्यमंत्री का नाम लिया गया है और न ही पार्टी के किसी नेता का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि करीब तीन वर्ष पहले शिवसेना और एनसीपी, इन दोनों दलों में जो फूट पड़ी थी, उस पर कुणाल कामरा ने यह कहकर तंज कसा था कि शिवसेना से शिवसेना निकल गयी और एनसीपी से एनसीपी निकल गयी। साथ ही उन्होंने शिंदे को संकेतों में गद्दार कहा। राज्य की भाजपा–शिवसेना (शिंदे गुट) व एनसीपी (अजित पवार गुट) की सरकार तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को कुणाल की कॉमेडी ऐसी नागवार गुजरी कि उन्होंने आयोजन स्थल में जमकर तोड़फोड़ की। जिस के बाद 11 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। उधर पुलिस ने शिवसेना विधायक व पार्टी प्रवक्ता मुरजी पटेल की शिकायत के आधार पर कुणाल कामरा के खिलाफ को एफआईआर दर्ज की। इतना ही नहीं, मुम्बई महानगरपालिका का एक दस्ता क्लब को जमींदोज करने हेतु भेजा गया। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कामरा की कॉमेडी को अपमानजनक बतलाते हुए कहा कि श्यह सहन नहीं किया जायेगा।श जबकि शिवसेना विधायक और मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि तोड़फोड़ जैसे काम का वह सरकार में होने के नाते समर्थन नहीं करते, लेकिन मंत्री होने से पहले वे शिवसैनिक हैं और जो हमारे नेता का मजाक उड़ाएगा उसे शिवसैनिक छोड़ेंगे नहीं। इस घटना पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का खून उबाल मार रहा है और नेता उसे जायज ठहरा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि कुणाल को महाराष्ट्र ही नहीं हिन्दुस्तान भर में कहीं भी घूमने–फिरने नहीं दिया जायेगा। ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के का कहना है कि कामरा एक अनुबंधित कॉमेडियन हैं। मगर उन्हें सांप की पूंछ पर पैर नहीं रखना चाहिए था। एक बार जब नुकीले दांत बाहर आते हैं तो परिणाम भयंकर होते हैं। म्हस्के ने आरोप लगाया कि कामरा ने उद्धव ठाकरे से पैसे लिए हैं और एकनाथ शिंदे को निशाना बना रहे हैं।श उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे देश में कहीं भी घूम न सकें। हम दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। अगर हम उनका अनुसरण करने लगे तो कामरा को देश छोड़ना पड़ेगा। गौरतलब है कि कुणाल कामरा समकालीन परिघटनाओं और राजनीति को अपने व्यंग्य के विषय बनाते हैं। एक मायने में उन्हें साहसी व चौतन्य कलाकार माना जाता है जो देश–विदेश की घटनाओं पर अपने तरीके से अपनी राय जाहिर करते हैं। स्टैंडअप कॉमेडी के अलावा वे सोशल मीडिया के जरिये भी सक्रिय रहते हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें इस नाते कई लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रसिद्ध हस्तियों से वे उलझ भी चुके हैं। 2020 में इंडिगो की एक फ्लाइट में उनकी मुलाकात सत्ता समर्थक माने जाने वाले एंकर अर्नब गोस्वामी से जब हुई तो उन्होंने गोस्वामी की पत्रकारिता पर तीखे सवाल किये। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। अर्नब गोस्वामी ने कामरा की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया तो कॉमेडियन ने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया कि वे सबसे सवाल तो पूछते हैं लेकिन खुद की बारी आयी तो चुप्पी साध गये। हालांकि इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें कई एयरलाइंस ने अलग–अलग अवधियों के लिये बैन कर दिया था। कुछ ने आजीवन प्रतिबन्ध लगा रखा है। ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविश अग्रवाल से उनकी सोशल मीडिया पर भिड़ंत होती रहती है। भाविश ने जब ओला गीगा फैक्ट्री की एक फोटो शेयर की तो उसके जवाब में कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की फोटो डाल दी थी और कंपनी की सेवाओं पर सवाल खड़े किये थे। 2022 में हरियाणा के गुरुग्राम में उनके शो को बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद ने रद्द करा दिया था। खुद को वीएचपी से बड़ा हिंदू बतलाते हुए कामरा ने वीएचपी को लिखे पत्र में नाथूराम गोडसे की निंदा करने हेतु ललकारा था। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का छेड़छाड़ से एडिटेड वीडियो जारी कर दिया था। हालांकि उन्होंने उसे हटा दिया था पर वे सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नजरों में आ गये थे। बाल संरक्षण आयोग ने भी उन्हें इसके लिये चेतावनी जारी की थी। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने से उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की तैयारी थी।

न्यायपूर्ण परिसीमन की लड़ाई!

राजेंद्र शर्मा

हैरानी की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी करनियों और अकरनियों से इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में उत्तर और दक्षिण के पुराने विभाजन को फिर से भड़का दिया है। जैसाकि हमने इससे पहले एक लेख में जिक्र किया था, इस विभाजन को बढ़ाने का काम मौजूदा केंद्र सरकार की भाषा नीति और शिक्षा रीति–नीति ने किया है। केंद्र सरकार के, शिक्षा के लिए तमिलनाडु राज्य के फंड उल्लेखनीय पैमाने पर रोकने ने इस टकराव को तेज किया और केंद्र सरकार के इसके ऐलान ने इस टकराव को विस्फोटक बिंदु पर पहुंचा दिया कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष रूप से त्रिभाषा फार्मूले को जब तक तमिलनाडु लागू नहीं करता है, उसको रुका हुआ फंड नहीं दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने, जो त्रिभाषा फार्मूले को तमिलनाडु समेत गैर–हिंदीभाषी इलाके पर हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देखती है, न सिर्फ फंड रोकने के डंडे के बल पर केंद्र की शिक्षा नीति तथा भाषा नीति थोपने की इन कोशिशों को ठुकरा दिया बल्कि अवज्ञापूर्ण रुख अपनाते हुए, केंद्र की इस मनमानी का हर कीमत पर विरोध करने का भी ऐलान कर दिया। इसी दौरान, मोदी सरकार के इरादों को लेकर गंभीर आशंकाओं से भड़के एक और मुद्दे ने, उत्तर–दक्षिण के विवाद को और उग्र बना दिया है। यह मुद्दा है, आने वाले समय में होने वाली जनगणना के बाद, होने वाले परिसीमन या जन–प्रतिनिधित्व की इकाई के रूप में लोकसभाई क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन का। जन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक समायोजन की व्यवस्था करते हुए, देश के संविधान में इसका प्रावधान किया गया था कि हरेक दस साला जनगणना के बाद, उसके आधार पर संसदीय क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जाए, ताकि इस दौरान आए जनसांख्यिकीय बदलावों को हिसाब में लिया जा सके। इन बदलावों के लिए दो अलग–अलग स्तरों पर, परिसीमन के जरिए परिवर्तन किए जाते हैं। राज्यों के स्तर पर यानी राज्यों के अंदर परिवर्तन और राज्यों के बीच में परिवर्तन। इसी आधार पर, दशकीय जनगणना को आधार बनाकर, पहला परिसीमन 1952 में हुआ था और उसके बाद 1963 तथा 1973 में परिसीमन हुआ था और इसके जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या क्रमशरू 494, फिर 522 और फिर 543 तय की गयी थी। बहरहाल, 1976 में एक संविधान संशोधन के जरिए, परिसीमन की प्रक्रिया को 25 साल के लिए स्थगित कर दिया गया और लोकसभा की सीटों की संख्या को तब तक के जहां का तहां रोक दिया गया। इसके पीछे विचार यह था कि जिन राज्यों में आबादी ज्यादा बढ़ रही थी, उन्हें इसी के बल पर लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के जरिए प्रोत्साहित नहीं किया जाए। बहरहाल, इसके बाद यानी 2001 की जनगणना के बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों के कड़े विरोध के सामने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी सीटों की कुल संख्या के लिहाज से परिसीमन पच्चीस साल और यानी 2026 तक रोके रखने और सीटों की संख्या जहां की तहां बनाए रखने का कदम उठाना पड़ा था। इसके बाद, परिसीमन आयोग का गठन तो किया गया, लेकिन उसे जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्यों की सीमाओं के अंदर ही सीमित परिसीमन करना था। 2026 के बाद होने वाले इसी पूर्ण परिसीमन ने दक्षिण भारतीय राज्यों और अन्य गैर–हिंदीभाषी राज्यों की भी इसकी आशंकाओं को भड़का दिया है कि यह परिसीमन, लोकसभा की उनकी सीटों की संख्या के रूप में, उनका राजनीतिक वजन घटाने का औजार बनने जा रहा है। इसका कारण आसानी से समझा जा सकता है। आबादी में वृद्घि की दर कम करने के मामले में, दक्षिण भारतीय राज्यों और उत्तर भारतीय राज्यों के बीच अब भी बहुत भारी अंतर बना हुआ है। यह अंतर बेशक घटा है, फिर भी उल्लेखनीय रूप से बड़ा बना हुआ है और इन पचास वर्षों में आबादी वृद्घि दरों से आबादियों के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे हालात में यदि आबादी के आधार पर ही परिसीमन किया जाता है, तो संसदीय प्रतिनिधित्व के अनुपात के लिहाज से गैर–हिंदी प्रदेशों का राजनीतिक वजन उल्लेखनीय तरीके से घट जाएगा और हिंदी भाषी क्षेत्र का राजनीतिक वजन उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। ऐसा होने में आज केंद्र में सत्ता में बैठे संघ–भाजपा को राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है क्योंकि गैर–हिंदी क्षेत्र ही उनका मजबूत राजनीतिक गढ़ है, जबकि खासतौर पर दक्षिणी भारत में उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। इस संबंध में वर्तमान सत्ताधारियों की नीयत को लेकर संदेह इसलिए और भी बढ़ जाते हैं कि उनके पसंदीदा प्रोजैक्ट के रूप में बनाये गए नये संसद भवन में, जिसकी संकल्पना में किसी व्यापक राजनीतिक परामर्श का कोई दखल नहीं था, भविष्यदृष्टि के नाम पर लोकसभा में 800 से ज्यादा सीटों की व्यवस्था रखी गयी है। यह इसका स्पष्ट संकेत करता है कि वर्तमान सरकार, परिसीमन के फलस्वरूप लोकसभा की सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाकर चल रही है। और जैसाकि हमने पीछे कहा, आबादी पर आधारित परिसीमन के जरिए सीटों की बढ़ोतरी का अर्थ होगा, हिंदी–भाषी क्षेत्र का संसदीय वजन उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाना और विशेष रूप से दक्षिण का वजन उसी अनुपात में घट जाना। इस सिलसिले में विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों की गंभीर आशंकाओं तथा चिंताओं को एक हद तक शांत करने की कोशिश में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही हफ्ते पहले, तमिलनाडु के अपने एक दौरे के क्रम में यह आश्वासन दिया था कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिसीमन से किसी भी राज्य की सीटें घटेंगी नहीं बल्कि सभी की सीटों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने श्आनुपातिक आधार परस्चय सीटें तय किए जाने का भरोसा दिलाया था। लेकिन, शाह का यह आश्वासन भी गैर–हिंदी राज्यों की आशंकाओं को दूर करने के लिहाज से नाकाफी ही साबित हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि शाह के आश्वासन से यह स्पष्ट नहीं है कि अनुपात के आधार परस्चय से उनका ठीक–ठीक आशय क्या है? मुद्दा यह नहीं है कि हिंदी राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी और गैर–हिंदी राज्यों की सीटें घट जाएंगी। मुद्दा यह है कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी किस आधार पर होगी। अगर यह बढ़ोतरी चालू आबादी के आधार पर की जाती है, तो कुल मिलाकर गैर–हिंदी राज्यों की सीटों का अनुपात, उसके वर्तमान अनुपात से घट जाएगा। गैर–हिंदी राज्य लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में अपने वर्तमान अनुपात को बनाए रखे जाने की मांग कर रहे हैं और अमित शाह और उनके संगी, इसी का आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हैं। जाहिर है कि वे आबादी पर आधारित परिसीमन के अनार्जित फायदे हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसी पृष्ठ्ङ्भूमि में 22 मार्च को चेन्नै में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की पहल पर, प्रस्तावित परिसीमन से चिंतित राज्यों के नेताओं का जमावड़ा हुआ। इस मुद्दे पर तमिलनाडु की, अपवादस्वरूप भाजपा को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करने के बाद, स्टालिन ने और वृहत्तर राजनीतिक एकता के लिए पहल की है। यह पहल कोआर्डीनेशन कमेटी फॉर फेअर डिलिमिटेशन नाम के मंच के माध्यम से की गयी है। यह इस मंच की पहली ही बैठक थी जिसमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना तथा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के अलावा कर्नाटक के उप–मुख्यमंत्री और ओडिशा की मुख्य विपक्षी पार्टी, बीजू जनता दल के सुप्रीमो, नवीन पटनायक और तेलंगाना की प्रमुख विपक्षी पार्टी, बीआरएस के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक ने एक स्वर से यह मुद्दा उठाया है कि आबादी के अनुपात के आधार पर राज्यों का लोकसभा का प्रतिनिधित्व तय करना, विशेष रूप से दक्षिण भारत के उन राज्यों को दंडित करना होगा, जिन्होंने राष्ट्रीय आबादी नीति के पालन में और अन्य अनेक मानकों पर प्रगति में, हिंदी–भाषी राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। उन पहलुओं से अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सजा देना और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सीटों या उनके अनुपात में बढ़ोतरी के रूप में ईनाम दिया जाना, तो न्यायपूर्ण परिसीमन नहीं है।

आग जो कभी लगी नहीं और छिपा हुआ धन जो कभी मिला नहीं

के रवींद्रन

यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से नकदी का एक बड़ा जखीरा मिलने से सभी सदमे में हैं। इस अप्रत्याशित घटना ने न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बारे में असहज सवाल खड़े कर दिये हैं, जिसे अक्सर न्याय और नैतिक सदाचार का संरक्षक माना जाता है। जबकि यह घटना अपने आप में निंदनीय है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह प्रणालीगत सड़ांध की ओर इशारा करती है– एक ऐसी गहरी और खतरनाक वास्तविकता जिसे बहुत लंबे समय से अनदेखा किया गया है या अनदेखा किया जा रहा है। पैसे के छिपे हुए भंडार जो शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, और वे अपारदर्शी गलियारे जहां न्याय का वितरण माना जाता है, बहुत गहरी अस्वस्थता की ओर इशारा करते हैं। यह घटना सिर्फ एक जज या अवैध रूप से अर्जित धन के एक भंडार के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत की न्यायिक प्रणाली की मूल संरचना में मौजूद परेशान करने वाली दरारों को दर्शाती है। इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया संस्थान के सतर्क और अक्सर स्व–नियमन के प्रति गैर–प्रतिबद्ध दृष्टिकोण की विशेषता थी। शुरुआती रिपोर्टों में निर्णायक कार्रवाई का संकेत दिया गया था, जिससे उम्मीद जगी थी कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरकार एक कड़ा रुख अपना सकता है। हालांकि, जैसे–जैसे दिन बीतता गया, यह स्पष्ट होता गया कि प्रतिक्रिया वास्तविक से ज्यादा प्रतीकात्मक होगी, जो न्यायपालिका के असुविधाजनक विवादों को दरकिनार करने के इतिहास के अनुरूप होगी। भ्रष्टाचार का सीधे सामना करने की यह अनिच्छा एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। कदाचार के आरोप, यहां तक कि जब सर्वोच्च न्यायिक पदों पर बैठे लोगों पर निर्देशित होते हैं, तो अक्सर इंकार, विक्षेपण या चुप्पी के साथ सामना किया जाता है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का डर जवाबदेही और पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता को खत्म कर देता है। पिछले कुछ वर्षों में, कई प्रमुख हस्तियों ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उनकी चेतावनियां मोटे तौर पर अनसुनी रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण से लेकर उनके बेटे प्रशांत भूषण तक, साहसी आवाजों ने न्यायिक प्रणाली के अंधेरे पक्ष को उजागर करने की कोशिश की है। सर्वोच्च न्यायिक मंचों के समक्ष लगाये गये उनके आरोपों ने आक्रोश को जन्म दिया है, लेकिन शायद ही कभी सार्थक सुधार हुआ हो। न्यायपालिका की अपने घर को साफ करने की स्पष्ट अनिच्छा एक संस्थागत जड़ता को दर्शाती है जो न्याय की नींव को ही खतरे में डालती है। भ्रष्टाचार के आरोपों को नजरअंदाज या दबाकर, न्यायपालिका जनता के भरोसे को खत्म करने का जोखिम उठाती है–एक ऐसा भरोसा जो कानून के शासन के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जरूरी है। यशवंत वर्मा का मामला विशेष रूप से परेशान करने वाला है क्योंकि यह न्यायिक निष्पक्षता के आदर्श को कमजोर करता है। उनके आवास में मिली नकदी की हर गड्डी न्याय की संभावित विफलता का प्रतिनिधित्व करती है – एक ऐसा मामला जिसका फैसला कानूनी तर्कों के गुण–दोष के आधार पर नहीं बल्कि छिपे हुए वित्तीय प्रोत्साहनों के आधार पर किया गया हो सकता है। इस तरह का भ्रष्टाचार न्यायिक प्रक्रिया को विकृत करता है, खतरनाक मिसाल कायम करता है जो मुकदमेबाजों की भावी पीढ़ियों को परेशान कर सकता है। जब फैसले रिश्वत या व्यक्तिगत लाभ से प्रभावित होते हैं, तो पूरी कानूनी व्यवस्था से समझौता हो जाता है, और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत निरर्थक हो जाता है। भारत की न्यायपालिका में व्यवस्थागत दोष रेखाएं नयी नहीं हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। फैसले सुनाने में देरी, अस्पष्ट न्यायिक नियुक्तियां, जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने कानूनी व्यवस्था से मोहभंग की भावना को बढ़ाने में योगदान दिया है। न्यायपालिका, जिसे न्याय चाहने वालों के लिए उम्मीद का आखिरी गढ़ माना जाता है, अब कई लोग इसे समाधान के बजाय समस्या का हिस्सा मानते हैं। यह धारणा लोकतंत्र में विशेष रूप से हानिकारक है, जहां न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों को बनाये रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।न्यायिक भ्रष्टाचार को संबोधित करने में प्रमुख चुनौतियों में से एक जवाबदेही के लिए प्रभावी तंत्र की अनुपस्थिति है। भारत में न्यायाधीशों को काफी स्वायत्तता प्राप्त है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से उनकी स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि, स्व–नियमन के संदर्भ में व्यक्त की गयी इस स्वायत्तता ने बाहरी निगरानी की कमी को भी जन्म दिया है, जिससे भ्रष्टाचार को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन मिल गयी है। न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने की आंतरिक प्रक्रियाएं अक्सर अपारदर्शी और अपर्याप्त होती हैं, और गोपनीयता की एक व्यापक संस्कृति है जो गलत न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराना मुश्किल बनाती है। न्यायिक भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करने वाले व्हिसलब्लोअर अक्सर प्रतिशोध का सामना करते हैं, जिससे पारदर्शिता और भी हतोत्साहित होती है। भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए न्यायपालिका की अनिच्छा भारतीय सार्वजनिक जीवन में व्याप्त दंड से मुक्ति की व्यापक संस्कृति से और भी जटिल हो जाती है। भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं हैय यह एक प्रणालीगत समस्या है जो सरकार की सभी शाखाओं को प्रभावित करती है। हालांकि, संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका भ्रष्टाचार में इसकी मिलीभगत को विशेष रूप से गंभीर बनाती है। जब न्यायाधीशों पर स्वयं भ्रष्टाचार का संदेह होता है, तो वे भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। ऐसा करने से यह संदेश जाता है कि कोई भी वास्तव में जवाबदेह नहीं है और न्याय की खोज निरर्थक है। यह निराशावाद पूरी कानूनी व्यवस्था की वैधता को कमजोर करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है। न्यायपालिका में सुधार करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर भारत को अपनी लोकतांत्रिक साख बनाये रखनी है तो यह जरूरी है।एक संभावित समाधान न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना है। इस निकाय को अन्य देशों में समान संस्थानों पर आधारित किया जा सकता है, जो न्यायिक स्वतंत्रता को बनाये रखते हुए न्यायिक भ्रष्टाचार को रोकने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव–स्ट्रीमिंग और न्यायाधीशों की संपत्ति का प्रकाशन शामिल है, न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने में मदद कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण कदम न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना है।

नेहा कक्कड़ के माता-पिता उनका गर्भपात कराना चाहते थे, भाई टोनी कक्कड़ ने वीडियो में किया था खुलासा, जानें कैसे बच गयी सिंगर

खून और संगीत से जुड़े कक्कड़ भाई–बहनों की तिकड़ी, जिसमें सोनू कक्कड़, टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ शामिल हैं, ने प्रसिद्धि और सफलता के लिए नीचे से नीचे तक संघर्ष किया है। जहाँ टोनी और नेहा लाइमलाइट का आनंद लेते हैं, वहीं उनकी बड़ी बहन सोनू अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कम ही बात करती हैं। संगीत की दुनिया पर राज करते हुए, सोनू, टोनी और नेहा पेशेवर और व्यक्तिगत मोर्चे पर भी ऊँचे मुकाम पर हैं। नेहा कक्कड़ का एक अंडरडॉग से लेकर अब सबसे सफल, अमीर और लोकप्रिय बॉलीवुड सिंगर्स में से एक बनने तक का सफ़र प्रेरणादायक है। वैसे, उन्होंने इंडियन आइडल की प्रतियोगी के रूप में शुरुआत की और अब वे इसके जजों में से एक बन गई हैं। वैसे, नेहा के नाम कई चार्टबस्टर गाने हैं; आँख मारे, ओ साकी साकी, कल्ला सोहना नहीं, कोका कोला गाना, धीमे धीमे, गर्मी, दिलबर और काला चश्मा कुछ ऐसे गाने हैं। हालाँकि, यह हमेशा उनके लिए आसान नहीं था। कल नेहा के जन्मदिन पर जारी एक हालिया वीडियो में, उनके भाई टोनी कक्कड़ ने खुलासा किया कि कैसे उनके माता–पिता उनका गर्भपात कराना चाहते थे। नेहा कक्कड़ हाल ही में तब सुर्खियों में आईं जब मेलबर्न कॉन्सर्ट में तीन घंटे देरी से पहुंचने पर उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा। मंच पर गिरने के कारण उन्हें और भी डांटा गया। बहुत भावुक हो जाने की आदत के कारण, अभिनेत्री को अक्सर लोगों द्वारा चिढ़ाया जाता रहा है। हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि गायिका और उनके परिवार को अपनी मौजूदा स्थिति हासिल करने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ा। इसके अलावा, उनके भाई टोनी कक्कड़ ने खुलासा किया कि उनके माता–पिता नेहा का गर्भपात कराना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। इसके बारे में बात करते हुए, कक्कड़ भाई–बहनों ने स्टोरी ऑफ़ कक्कड़ शो बनाया, जिसमें उनके जीवन की चुनौतियों और बड़े होने के वर्षों पर चर्चा की गई। एपिसोड में चर्चा की गई कि कैसे उनके परिवार ने गुजारा करने के लिए संघर्ष किया और कैसे उनके माता–पिता ने उन्हें पालने और खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए बहुत मेहनत की। कक्कड़ भाई–बहन, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और सोनू कक्कड़ ने जगराते और अन्य अवसरों पर भजन गाकर पैसे कमाए। स्टोरी ऑफ़ कक्कड़ के दूसरे एपिसोड में, जो 5 जून, 2020 को नेहा कक्कड़ के जन्मदिन के एक दिन पहले प्रसारित हुआ, उनके भाई टोनी कक्कड़ ने रैप में उनके जन्म से जुड़ी घटनाओं का खुलासा किया। उन्होंने एपिसोड की शुरुआत श्हालात इतने खराब थे, खाली खाली से हाथ थे, ना ज़्यादा पढ़े लिखे, भोले से माँ बाप थेश रैप करके की। इसने उनके परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को उजागर किया। इसके अलावा, गायक ने अपनी बहन नेहा कक्कड़ के जन्म से पहले की घटनाओं के बारे में रैप किया। उसे याद है कि कैसे उसके माता–पिता नेहा का गर्भपात कराना चाहते थे क्योंकि वे बहुत गरीब थे। हालाँकि, वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इंडियन आइडल की माँ आठ सप्ताह की गर्भवती थी। टोनी कक्कड़ ने आगे कहा, श्पैसे नहीं होते थे, रातों में वो रोते थे, गर्भ था गिराना, पर पिछले हफ़्ते 8 थे, गर्मी का महीना, दिन था 6 जून का, शाम ढल रही थी जनम हुआ जुनून का।श जुनून अपनी बहन नेहा कक्कड़ का ज़िक्र कर रहे थे, जो अपनी गायकी से सनसनी बन गई हैं।

> संगीत की दुनिया पर राज करते हुए, सोनू, टोनी और नेहा पेशेवर और व्यक्तिगत मोर्चे पर भी ऊँचे मुकाम पर हैं। नेहा कक्कड़ का एक अंडरडॉग से लेकर अब सबसे सफल, अमीर और लोकप्रिय बॉलीवुड सिंगर्स में से एक बनने तक का सफ़र प्रेरणादायक है। वैसे, उन्होंने इंडियन आइडल की प्रतियोगी के रूप में शुरुआत की और अब वे इसके जजों में से एक बन गई हैं।

हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद फिर से प्यार की खोज में नताशा, बोलीं- जिंदगी हमेशा प्लान...

नताशा स्टेनकोविक ने शादी के 4 साल बाद क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से तलाक ले लिया है। दोनों के तलाक ने काफी सुर्खियां बटोरी थी जुलाई 2024 में दोनों ने हमेशा के लिए अपनी राहें अलग कर ली हैं। हार्दिक और नताशा का एक बेटा अगस्त्य है जो अपनी मां के पास रहता है। तलाक के बाद से ही हार्दिक के विदेशी सिंगर के साथ अफेयर के चर्चे हो रहे हैं। वहीं अब नताशा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दूसरे प्यार को मौका देने के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा–मैं प्यार में पड़ने के खिलाफ नहीं हूं। मैं लाइफ में जो भी आए उसे एक्सेप्ट करना चाहती हूं। मेरा मानना छ्है कि सही समय आने पर सही रिश्ते अपने आप बनते हैं। मैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप को महत्व देती हूं, जो विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। मुझे लगता है कि प्यार को मेरी सफर की तारीफ करनी चाहिए न कि उसे परिभाषित करना चाहिए। नताशा ने मूवऑन और माफी पर कहा–श्असफलताओं को असफलता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसे अनुभवों के रूप में देखा जाना चाहिए जो कुछ बेहतर करने की ओर ले जाते हैं। लाइफ हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है। दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करने से सिर्फ शख्स की शांति खराब होती है और यह इसके लायक नहीं है, बस माफ कर देना और आगे बढ़ जाना।

कॉमेडियन कुणाल कामरा की स्पोर्ट में उतरी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, एकनाथ शिंदे पर किया तीखा हमला

स्टैंड–अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक विवादित कमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, हालांकि शिंदे का नाम उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिया था। इस टिप्पणी के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच, अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कामरा के समर्थन में सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर की। एक पोस्ट में उन्होंने कुणाल कामरा की तस्वीर के साथ ट्रुथ लिखा। वहीं, दूसरी पोस्ट में स्वरा ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने हैबिटेट क्लब का जिक्र करते हुए लिखा, एकनाथ शिंदे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हैबिटेट मुंबई के बाकी हिस्सों की तरह दिखे। इससे पहले, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता राहुल कनाल के खिलाफ भी मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। खार स्थित ऑफिस में विरोध प्रदर्शन हुआ था और कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की थी। इसके बाद, पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कुणाल कामरा ने रविवार को अपने यूट्यूब चौनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी की। इस वीडियो में उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए उन्हें 'गद्दार' बताया था। इसके बाद, शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कामरा के खिलाफ विरोध जताया और खार स्थित कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। कामरा ने एक वीडियो में दिल तो पागल है गाने की तर्ज पर शिंदे का मजाक उड़ाया था। इस वीडियो में कामरा ने एकनाथ शिंदे की 2022 की बगावत का जिक्र किया, जिससे शिवसेना दो गुटों में विभाजित हो गई थी। इस टिप्पणी के बाद यह मामला अब राजनीति और समाज के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि कई इसे अपमानजनक और आपत्तिजनक करार दे रहे हैं।

ऑस्कर विनर फिलिस्तीनी फिल्ममेकर हमदान बल्लाल पर हमला, इजरायली सेना ने हिरासत में लिया

डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड के लिए इसी साल ऑस्कर जीतने वाले फिलिस्तीनी फिल्ममेकर हमदान बल्लाल को इजरायली सेना ने हिरासत में ले लिया है। हमदान, इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक गांव में अपने घर के आसपास थे जब इजरायली लोगों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। इजरायली शेल्टर्स के इस हमले के बाद इजरायली सेना भी वहां पहुंची और फिल्ममेकर को हिरासत में ले लिया। डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड के इजरायली को–डायरेक्टर युवल अब्राहम ने इस घटना की पुख्ता भास्करष्ट की है। उन्होंने लिखा, शेल्टर्स के एक समूह ने हमारी फिल्म नो अदर लैंड के को–डायरेक्टर हमदान बल्लाल को खूब पीट है। उनके सिर और पेट में चोटें आईं, खून बह रहा था। सैनिकों ने उनके द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस पर भी हमला किया और उसे ले गए। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। एक रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्री के को–डायरेक्टर बेसल अद्रा ने हमदान बल्लाल को हिरासत में लेकर जाते हुए देखा। उन्होंने बताया कि लगभग दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने गांव पर हमला किया, जबकि इजरायली वर्दी पहने सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर अपनी बंदूकें तान दीं। बेसल अद्रा ने बताया, हम ऑस्कर से वापस आए और तब से हर दिन हम पर हमले हो रहे हैं। युवल अब्राहम ने इस बीच एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कुछ नकाबपोश लोग एक कार पर पत्थर बरसा रहे हैं। उन्होंने लिखा, नो अदर लैंड के निर्देशक हमदान बल्लाल (अभी भी लापता) पर हमला करने वाले केकेके जैसे हथियारबंद नकाबपोश लोगों का समूह कैमरे में कैद हुआ। डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड के लिए, हमदान बल्लाल ने युवल अब्राहम और साथी फिलिस्तीनी फिल्म निर्माता बेसल अद्रा और इजरायली सिनेमेटोग्राफर, एडिटर और डायरेक्टर राहेल सोर के साथ मिलकर काम किया। बता दें कि नो अदर लैंड का वर्ल्ड प्रीमियर 2023 बर्लिनले में हुआ था, जहां इसने ऑडियंस अवॉर्ड और बर्लिनले डॉक्यूमेंट्री अवॉर्ड जीता। युवल अब्राहम ने अपने भाषण में इजरायल में रंगभेद की स्थिति की आलोचना करने और गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया था जिस कारण विवाद हो गया था। युवल अब्राहम को मौत की धमकियां मिली हैं और उन पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया गया।

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद का हाईवे पर एक्सीडेंट...

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की पत्नी, सोनाली सूद, मुंबई–नागपुर समृद्धि हाईवे पर एक सड़क हादसे में घायल हो गई हैं। हालांकि, करीबी सूत्रों के मुताबिक, दुर्घटना गंभीर नहीं थी और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, जिसके लिए चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हादसे में सोनू की साली को भी चोटें आई हैं और फिलहाल दोनों का इलाज नागपुर के एलेक्सिस हॉस्पिटल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोनू सूद नागपुर पहुंच गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दुर्घटना 25 मार्च 2025 को हुई, हालांकि हादसे के कारण और सोनाली की चोटों के बारे में अब तक अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। सोनू सूद ने इस हादसे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि सोनू और सोनाली की शादी 1996 में हुई थी। सोनाली आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। पेशेवर तौर पर वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। इस जोड़ी के दो बेटे, आयान और इशांत हैं। सोनू और सोनाली सूद अपनी निजी जिन्दगी को आमतौर पर मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं।

रमजान में शोएब इब्राहिम ने मनाया सासू मां का बर्थडे, सेलिब्रेशन में पहुंचे दीपिका के ससुरालवाले

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम टीवी इंडस्ट्री के चर्चित स्टार कपल्स में से एक हैं। कपल काम में कितना भी बिजी क्यों ना हो परिवार के लिए समय निकाल ही लेते हैं। हाल ही में कपल के घर पर एक और खुशी का मौका था क्योंकि वे दीपिका की मां का जन्मदिन साथ में मना रहे थे। इस सेलिब्रेशन में परिवार के करीबी सदस्य शामिल हुए और सबने इसे हंसी, प्यार और टेस्टी खाने से भरी प्लेटों के साथ खुशी–खुशी मनाया। इस दिन को खास बनाने के लिए दीपिका ने सबसे ज्यादा समय केक चुनने में लगाया और बहुत मेहनत की। उनके चौनल पर नए वीडियो में ये सारी झलक साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया, मां को पाईनेप्पल का स्वाद बहुत पसंद है। हमने पहले कभी चीजकेक नहीं खाया था, इसलिए मैंने उनमें से एक का ऑर्डर दिया, साथ ही एक छोटा बिस्कॉफ और एक छोटा तिरामिसू भी मंगाया। उन्होंने कहा, हम घर पर जश्न मना रहे हैं लेकिन बाद में हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। हम सभी को ईद की खरीदारी के लिए भी ले जा रहे हैं। जन्मदिन के जश्न के अलावा परिवार रमजान और इफ्तार के जश्न में व्यस्त है।

लेंट के दौरान शुक्रवार को मछली खाने की है परंपरा, घर पर ट्राई करें ये रेसिपी, मेहमानों को खूब आएगी पसंद

लेंट के दौरान शुक्रवार के खाने के लिए फिश का तलना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन कुछ बदलावों से यह यादगार हो सकता है। आप पारंपरिक मछली व्यंजनों के साथ क्लासिक जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में चीजों को मसालेदार बनाना चाहते हैं, तो फिश टैकोस और फिश राइस बाउल से बेहतर कुछ भी नहीं है।

लेंट के दौरान, ईसाई लोग शुक्रवार को घर पर फिश का खाना खाते हैं। इसका कारण यह है कि लेंट के दौरान गर्म–रक्त वाले जानवरों का सेवन करना मना है। इसलिए, लोग फिश खाते हैं क्योंकि यह ठंडे–रक्त वाला होता है। लेंट के दौरान शुक्रवार के खाने के लिए फिश का तलना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन कुछ बदलावों से यह यादगार हो सकता है। आप पारंपरिक मछली व्यंजनों के साथ क्लासिक जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में चीजों को मसालेदार बनाना चाहते हैं, तो फिश टैकोस और फिश राइस बाउल से बेहतर कुछ भी नहीं है। इन्हें आजमाएं और अपने शुक्रवार के खाने को यादगार बनाएं! फिश फ्राई चटनी के साथरू इस डिश को बनाने के लिए, सबसे पहले फिश के टुकड़ों को नमक, काली मिर्च, और नींबू के रस से मैरीनेट करें। फिर, एक पैन में तेल गरम करें और फिश के टुकड़ों को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसके बाद, एक मिक्सर में हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, और नींबू का रस मिलाकर चटनी बनाएं। फिश फ्राई को चटनी के साथ परोसें और इसका आनंद लें। यह एक स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाला व्यंजन है जो आपको जरूर पसंद आएगा। मीठा और खट्टा सैल्मन फिश सब्जियों के साथरू इस डिश को बनाने के लिए, सबसे पहले सैल्मन फिश के टुकड़ों को नमक, काली मिर्च, और चीनी से मैरीनेट करें। फिर, एक पैन में तेल गरम करें और फिश के टुकड़ों को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसके बाद, एक अलग पैन में हरी बीन्स को नमक, काली मिर्च, और नींबू के रस के साथ पकाएं। अंत में, फिश और हरी बीन्स को एक साथ मिलाएं और मीठा और खट्टा सॉस डालें। यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है जो आपको जरूर पसंद आएगा।

फिश टैकोसः इस डिश को बनाने के लिए, सबसे पहले फिश के टुकड़ों को नमक, काली मिर्च, और नींबू के रस से मैरीनेट करें। फिर, एक पैन में तेल गरम करें और फिश के टुकड़ों को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसके बाद, टैकोस की रोटियों पर फिश, प्याज, टमाटर, और धनिया रखें। ऊपर से नींबू का रस और सालसा डालें। आप चाहें तो इसमें अवोकाडो और सोर क्रीम भी डाल सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाला व्यंजन है जो आपको जरूर पसंद आएगा।

फिश राइस बाउलः इस डिश को बनाने के लिए, सबसे पहले चावल को पकाएं। फिर, फिश के टुकड़ों को नमक, काली मिर्च, और नींबू के रस से मैरीनेट करें। एक पैन में तेल गरम करें और फिश के टुकड़ों को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसके बाद, एक कटोरे में चावल, फिश, और अपनी पसंद की सब्जियां जैसे कि गाजर, मटर, और प्याज रखें। ऊपर से सोया सॉस और नींबू का रस डालें। यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है जो आपको जरूर पसंद आएगा।

लेंट के दौरान मछली खाने की परंपरा के पीछे की कहानी

लेंट के दौरान मछली खाने की परंपरा का मुख्य कारण यह है कि मछली को ठंडे–रक्त वाला जानवर माना जाता है। ईसाई धर्म में, गर्म–रक्त वाले जानवरों को लेंट के दौरान खाने से मना किया जाता है। मछली को ठंडे–रक्त वाला माना जाता है, इसलिए इसे लेंट के दौरान खाने की अनुमति है। यह परंपरा मध्य युग में शुरू हुई थी। आजकल, लेंट के दौरान मछली खाने की परंपरा विश्वभर में मनाई जाती है। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है।

ये लोग बिलकुल ना पीएं कॉफी, सेहत के लिए सिर्फ नुकसान!

अगर आप रोजाना कॉफी पीने की आदत से जूझ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कॉफी का स्वाद और खुशबू लोगों को ताजगी का अहसास कराते हैं, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कॉफी पीना अनहेल्दी और हानिकारक हो सकता है। जानिए किन लोगों को कॉफी से बचना चाहिए।

कॉफी पीने के फायदे

कॉफी कई लोगों के लिए एक दिन की शुरुआत होती है। यह काम के बीच ताजगी और एनर्जी देने के लिए फेमस है। कुछ रिसर्च्स के मुताबिक, थोड़ी मात्रा में कॉफी ब्रेन फंक्शन को बेहतर करने में मदद करती है। ब्लैक कॉफी पीने से वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद कैफीन शरीर में डोपामाइन (हैप्पी हार्मोन) के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आप रिलैक्स और ऊर्जा महसूस करते हैं।

कॉफी के नुकसान

हालांकि, अगर इसका सेवन ज्यादा किया जाए तो यह नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कप कॉफी भी साइड–इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। ऐसे में, आइए जानें किन लोगों को कॉफी से दूर रहना चाहिए।

हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज

जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें कॉफी से बचना चाहिए। कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर में उतार–चढ़ाव आ सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस स्थिति में, कॉफी पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों की कमजोरी) के मरीज

कॉफी पीने से हड्डियों की कमजोरी बढ़ सकती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा कॉफी पीने से बोन डेंसिटी कम हो सकती है और हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ सकता है।

गर्भावस्था में कॉफी से परहेज

प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कॉफी पीने से बचना चाहिए। कॉफी पीने से गर्भवती महिला के ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी हो सकती है और भ्रूण के विकास पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

एंग्जायटी डिसऑर्डर वाले लोग

जिन्हें एंग्जायटी (चिंता) की समस्या है, उनके लिए कॉफी हानिकारक हो सकती है। कॉफी पीने से पैनिक अटैक (चिंता का अधिक बढ़ना) हो सकता है। ऐसे में, कॉफी से पूरी तरह बचना चाहिए।

नोटः कॉफी पीने के कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन या कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए, यदि आपको इनमें से कोई समस्या है, तो कॉफी पीने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह जानकारी केवल सामान्य सलाह है, और किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना हमेशा अच्छा रहेगा।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी नसें कमजोर हैं? जानिए लक्षण, कारण और बचाव

नसें हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो को बाकी अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं लेकिन जब ये नसें कमजोर होती है तो शरीर में कई तरह की हैल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नसें कमजोर होने के भी बहुत सारे कारण हैं और सबसे मुख्य कारण आपका खान–पान ही है। अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो तो नसें कमजोर होने लगती हैं और ये नसें शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोर हो सकती है। कमजोरी को दूर करने के लिए डाइट में विटामिन्स– मिनरल्स और बाकी तत्व लेने जरूरी है।

नसों में कमजोरी है क्या?

नसों में कमजोरी होना, एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर समस्या है और यह कमजोरी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। कुछ लोगों में नसों की कमजोरी कुछ समय के लिए होती है जब वह डाइट व लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं तो अपने आप सही हो जाते हैं लेकिन कुछ लोगों में यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है और इलाज न मिलने पर मरीज की स्थिति गंभीर भी हो सकती है।

नसों में कमजोरी के लक्षण

नसों की कमजोरी में आपकी त्वचा पर मकड़ी जैसी नसें दिख सकती हैं या त्वचा के नीचे उभरी हुई महीन लाल–नीली रेखाओं के रूप में भी इसकी पहचान की जा सकती है। नसों की कमजोरी के कारण वैरिकोज वेन्स और थ्रोम्बोसिस भी बन सकते हैं। नसों में कमजोरी होने पर आपको कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं जैसे हाथ पैर में झुनझुनी या चुभन महसूस होना।

शरीर में कंपन महसूस होना।

पैरों में सूजन, भारीपन, थकान या दर्द।

मकड़ी जैसी नीली–लाल नसें दिखना।

नसों में दर्द और तनाव महसूस होना।

शरीर में एनर्जी ना रहना और बहुत अधिक कमजोरी महसूस होना।

पेट से जुड़ी परेशानियां या सिरदर्द।

बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड लगना।

ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां आना।

डिप्रेशन और स्ट्रेस महसूस होना।

मांसपेशियों में कमजोरी होना।

नसों में कमजोरी के कारण

खान–पान के अलावा भी नसों में कमजोरी आने के कुछ कारण हो सकते हैं चलिए उस बारे में भी आपको बताते हैं।

दुर्घटना या चोट लगने से नसों में सूजन आना, अगर चोट गंभीर है तो नसों में कमजोरी आ जाती है।

ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी, डायबिटीज,ऑटोइम्यून डिसीज, हॉर्मोन का असंतुलन जैसी दिक्कतें।

हर्पीज, एचआईवी, हेपेटाइटिस सी या कोई आनुवांशिक कारण

खान–पान की गलत आदतें जैसे एल्कोहन–धूम्रपान का अधिक सेवन करने वाले।

किडनी या लिवर से जुड़ी समस्या होने से भी नसें कमजोर हो सकती हैं।

ट्यूमर या कैंसर, कीमोथेरेपी की दवाएं लेने से भी नसें कमजोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में डाक्टर से पूछकर ही कोई दवाई या डाइट लें।

अगर नसों में कमजोरी खान–पान के चलते आई है तो संतुलित आहार खाने शुरू करें। आहार में फाइबर–आयरन, विटामिन्स का सेवन अधिक करें। विटामिन सी से भरपूर फल सब्जियां खाए ।आहार में ओटमील, ब्राउन राइस, ब्रोकली, एवोकाडो, दालें शामिल करें। डाइट में पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, फूलगोभी, पत्तागोभी, संतरा, नींबू, स्प्राउट्स इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। ओमेगा–3 फैटी एसिड जरूर लें। हल्दी वाला दूध पीएं।

जिन लोगों को ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है वो ओट्स जरूर खाएं। ओट्स बहुत हैल्दी माने जाते हैं। वह मेवों का सेवन करें। अखरोट–बादाम, किशमिश जैसे मेवे शरीर में जान डालने का काम करते हैं। अगर इसकी तासीर गर्म लगती हैं तो इनका सेवन भिगोकर करें। विटामिन ई से भरपूर चीजें जैसे कि नट्स, बीज वाली चीजें, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, पंपकिन, आम, मछली खाएं, विटामिन बी6 के लिए केला, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और विटामिन बी12 के लिए अंडे खाएं। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी जैसे जामुन फ्लेवोनॉयड्स और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। शरीर में पानी की कमी से थकान और कमजोरी हो सकती है इसलिए जरूरी है कि दिनभर में 2 से 3 लीटर पानी पिएं। फलों का जूस, छाछ, लस्सी, नींबू पानी और नारियल पानी भी पी सकते हैं।

तेल की मालिश करने से भी नसों को मजबूती मिलती है। तिल, अरंडी, देसी घी, सरसों का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल को हैल्दी रखें। फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखे। सैर करें योग करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। खुद को तनावमुक्त रखें। अच्छी नींद भी लें। इससे भी शारीरिक और मानसिक थकान से राहत मिलती है।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी नसें कमजोर हैं?

शरीर में सुन्नपन–झुनझुनाहट होना या किसी खास हिस्से में संवेदना या एहसास का खत्म हो जाना, इसके आम लक्षण है हालांकि यह कई अलग–अलग चिकित्सा रोगों का भी एक आम लक्षण है, लेकिन यह आमतौर पर शरीर की नसों में किसी समस्या का संकेत होता है।

कौन सा भोजन नसों को मजबूत बनाता है?

स्वस्थ आहार खाकर ही आप नसों को मजबूत बना सकते हैं। ओमेगा–3 फैटी एसिड भी नसों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मछली, एवोकाडो, अलसी और अखरोट में भरपूर ओमेगा–3 फैटी एसिड पाया जाता है।

कौन सा तेल नसों को मजबूत करता है?

नसों में दर्द और कमजोरी दूर करने के लिए अरंडी के तेल से मालिश करें। गर्म गुनगुने पानी में तेल डालकर सिंकाई करने से भी आराम मिल सकता है।

सेंधा नमक के पानी से सिंकाई

नसों को मजबूत बनाए रखने के लिए सेंधा नमक के पानी से सिंकाई करें। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट पाया जाता है, जो नसों को मजबूत कर सकता है। आप गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर नहा सकते हैं। इससे भी आराम मिलेगा।

हाथ पैरों की कमजोरी कैसे दूर करें?

एक से दो गिलास दूध का सेवन करने से बॉडी को भरपूर विटामिन बी 12 मिल सकता है। दूध ा नहीं पीते तो दही, पनीर या मट्ठे का सेवन करें। मशरुम का सेवन करें। मशरूम ऐसा फूड है जिसका सेवन करने से बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी पूरी होती है। इससे कमजोरी और थकान भी दूर होती है।

तुरंत ताकत के लिए क्या खाएं?

शरीर में तुरंत ताकत लाने के लिए अनार, केला, बादाम, अंडा, दही और डार्क चॉकलेट्स खाएं। डार्क चॉकलेट्स खाने से शरीर में तुरंत ही ऊर्जा का संचार होता है। इससे मूड भी बेहतर होता है।

नसों की कमजोरी दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय

नसों की कमजोरी के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं।

अश्वगंधाः अश्वगंधा पाउडर को एक गिलास दूध या पानी में मिलाकर पिया जा सकता है।

आंवलाः आंवले में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। आंवले के चूर्ण को आंवले के रस और मिश्री के साथ मिलाकर पानी या दूध के साथ पी सकते हैं।

चक्रफूल का तेलः नसों में बेचौनी और क्रैंप्स की समस्या ज्यादा है तो चक्रफूल के तेल की मालिश लाभदायक हो सकती है। नारियल या सरसों के तेल में चक्रफूल का तेल डालकर गर्म करें और रात में सोने से पहले लगाएं लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक उपाय करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें।

नोटः अगर नसों की कमजोरी किसी अन्य हैल्थ प्रॉब्लम या किसी रोग के चलते हैं तो डाक्टरी सलाह से अगला कदम उठाएं।

जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगे केकेआर और राजस्थान, जॉनसन की जगह नॉर्त्जे को मिलेगा मौका ?

गुवाहाटी, एजेंसी। हार के साथ आईपीएल 2025 सीजन की शुरुआत करने वाली गत चौंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और राजस्थान रॉयल्स की टीम की नजरें जीत की पटरी पर लौटने पर होगी। कोलकाता को पहले मुकाबले में रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से हार मिली, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान को हराया था। राजस्थान की टीम नियमित कप्तान के बिना उतर रही है। संजू सैमसन पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे थे और इस मैच में भी वह इसी भूमिका में उतर सकते हैं।

दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला

राजस्थान और केकेआर के बीच बराबरी का मुकाबला है। दोनों टीमों के हेड टु हेड की बात करें तो राजस्थान और केकेआर के बीच आईपीएल में अब तक कुल 29 मैच हुए हैं जिसमें ने दोनों ही टीमों ने 14–14 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। राजस्थान और कोलकाता की टीमें इस सीजन अपने पहले मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में आक्रामकता दिखाने में असफल रही। दोनों टीमें अब वापसी करना चाहेंगी।

केकेआर का पलड़ा भारी

राजस्थान और केकेआर दोनों ही टीमें अभी जीत का खाता नहीं खोल सकी हैं, लेकिन कागजों में केकेआर का पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कार्यवाहक कप्तान रियान पराग की भी परीक्षा होगी क्योंकि पहले मैच में वह कुछ फैसले करते हुए असमंजस की स्थिति में दिखे। राजस्थान के लिए नियमित कप्तान सैमसन ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरकर अच्छी बल्लेबाजी की थी और टीम को मैच में बनाए रखा था, लेकिन राजस्थान की टीम विशाल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी थी।

वरुण का खराब प्रदर्शन चिंता विषय

केकेआर के लिए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय है। ईडन गार्डंस की पिच पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने वरुण के खिलाफ आसानी से रन बटोरे। केकेआर को उम्मीद होगी कि वरुण राजस्थान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करें।

पिछले मैच में कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेन के आउट होने के बाद केकेआर का मध्यक्रम बिखर गया था। वेंकटेंश अय्यर और आंद्रे रसेल गलत शॉट खेलकर आउट हुए। टीम प्रबंधन को अब उम्मीद रहेगी कि वह शॉट चयन में सतर्कता बरतेंगे।

नॉर्त्जे की फिटनेस पर नजर

केकेआर की निगाह एनरिच नॉर्त्जे की फिटनेस पर भी टिकी रहेंगी जो पीठ की जकड़न से उबर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का यह तेज गेंदबाज अगर फिट घोषित होता है तो उन्हें स्पेंसर जॉनसन की जगह प्लेइंग–11 में शामिल किया जा सकता है। नॉर्त्जे का मैच में खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। अगर नॉर्त्जे फिट नहीं हुए तो इस बात की संभावना कम है कि केकेआर मैच के लिए प्लेइंग–11 में कोई खास बदलाव करे।

राजस्थान को गेंदबाजों से आस

राजस्थान की टीम को अगर वापसी करनी है तो उसके गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सनराइजर्स के खिलाफ पिछले मैच में उसके मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने चार ओवर में 76 रन लुटाए, जबकि फजल हक फारूकी और महेश थीक्षाना भी बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा पाए थे। इन सभी के पास गुवाहाटी में वापसी करने का मौका रहेगा।

इस मुकाबले के लिए केकेआर और राजस्थान की संभावित प्लेइंग–11 इस प्रकार है...

राजस्थान रॉयल्सः यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरॉन हेत्मायर, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, फजलहक फारुकी।

केकेआरः क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन/एनरिच नॉर्त्जे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती।

शतक नहीं, बड़ा स्कोर देख रहे थे श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह से आक्रमण जारी रखने को कहा; हुआ खुलासा

अहमदाबाद। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वह शतक लगाने से चूक गए क्योंकि अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने 23 रन जुटाए और स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके। श्रेयस 97 रन बनाकर नाबाद रहे और आईपीएल का अपना पहला शतक लगाने से तीन रन से पीछे रह गए। श्रेयस हालांकि, निजी उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। श्रेयस के शानदार प्रदर्शन के दम पर पंजाब ने पांच विकेट पर 243 रन बनाए और 11 रन से जीतने में सफल रहे। शशांक ने मोहम्मद सिराज के अंतिम ओवर में पांच चौके लगाए। शशांक ने 16 गेंदों पर 44 रन बनाए और नाबाद पवेलियन लौटे। शशांक ने कहा कि श्रेयस ने उनके स्ट्राइक रोटेट करने के लिए नहीं कहा था। मैच के बाद शशांक ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा था, लेकिन जब पहली गेंद पर मैंने चौका लगाया तो मेरा ध्यान गया कि श्रेयस 97 रन बनाकर खेल रहे हैं। शशांक ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन श्रेयस मेरे पास आए और बोले कि शशांक मेरे शतक की चिंता मत करो। मैं उनसे कहने वाला था कि क्या मैं आपको सिंगल दूं। श्रेयस ने जो कहा उसके लिए बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए क्योंकि जाहिर है कि टी20 में विशेषकर आईपीएल में आसानी से शतक नहीं बनते हैं। शशांक ने कहा कि श्रेयस का संदेश स्पष्ट था कि गेंदबाज पर आक्रमण जारी रखो। शशांक ने कहा, श्रेयस ने मुझसे कहा था कि शशांक हर गेंद को हिट करो और कोशिश करो कि चौका या छक्का मिले। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला। जाहिर है कि हम सभी जानते हैं यह एक टीम गेम है, लेकिन ऐसी स्थिति में स्वार्थ को हावी नहीं होने देना कठिन है। श्रेयस ने ऐसा किया। मैं उन्हें पिछले 10–15 वर्षों से जानता हूं। वह वैसे ही हैं और उन्होंने मुझसे शांत रहने और मैं जैसे शॉट खेलता हूं, वैसे शॉट खेलने के लिए कहा। मुझे लगता है कि हमने अच्छा फिनिश किया। वहीं, गुजरात टाइटंस के स्पिनर आर साई किशोर ने कहा कि उनकी टीम को लगा था कि वे मैच में आगे चल रहे हैं।

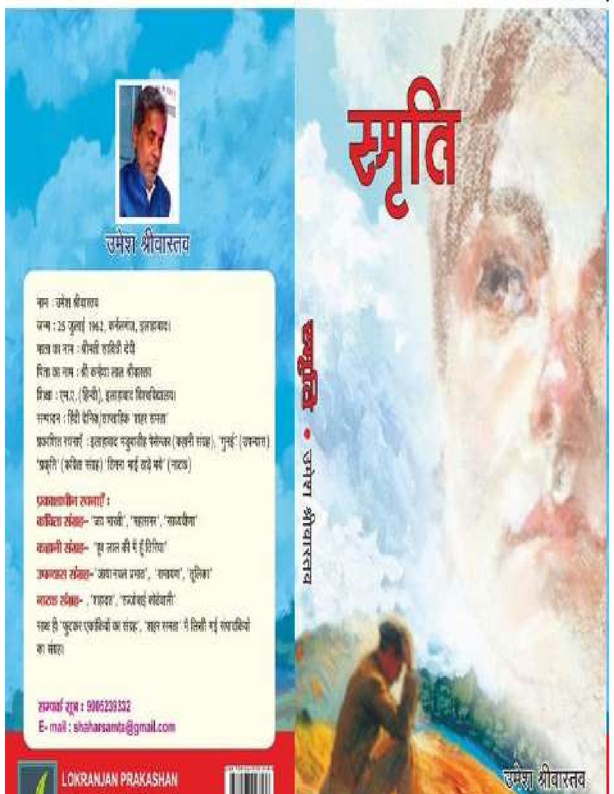

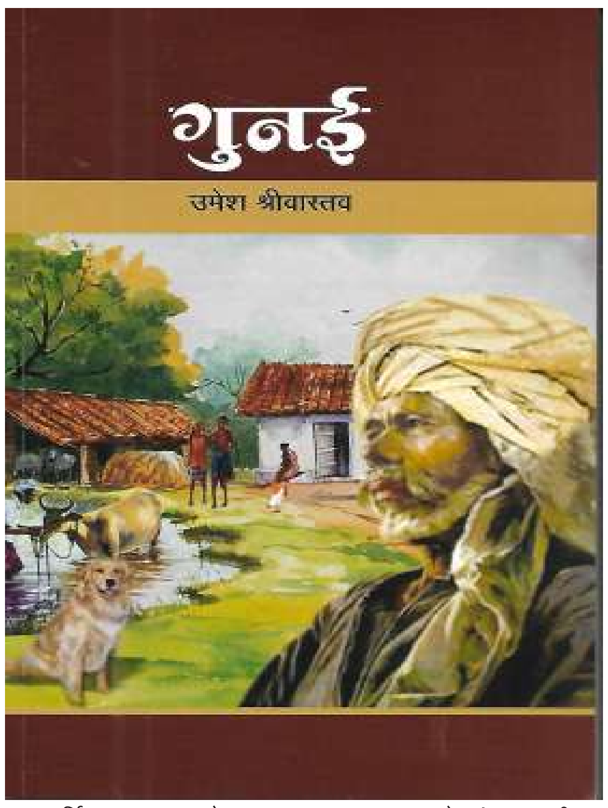

चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

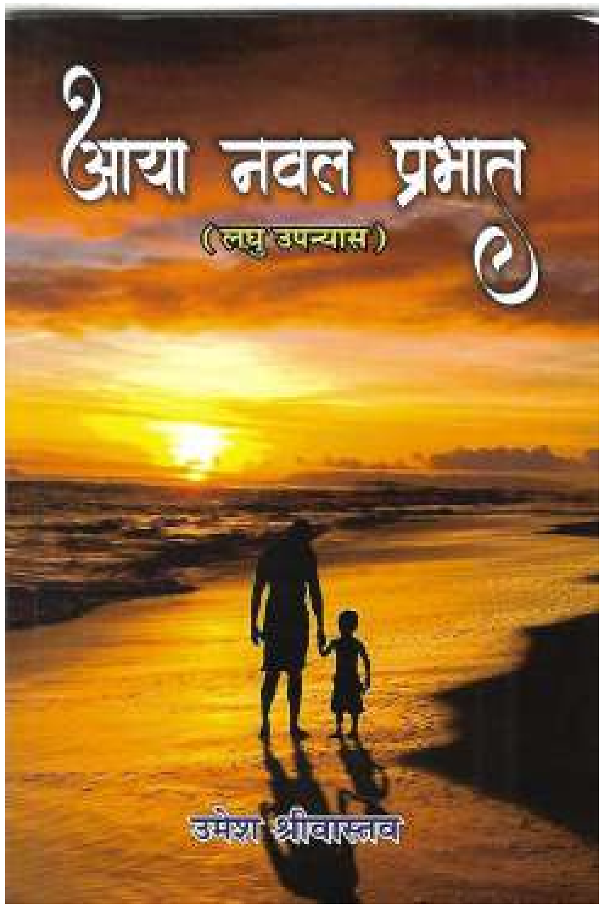

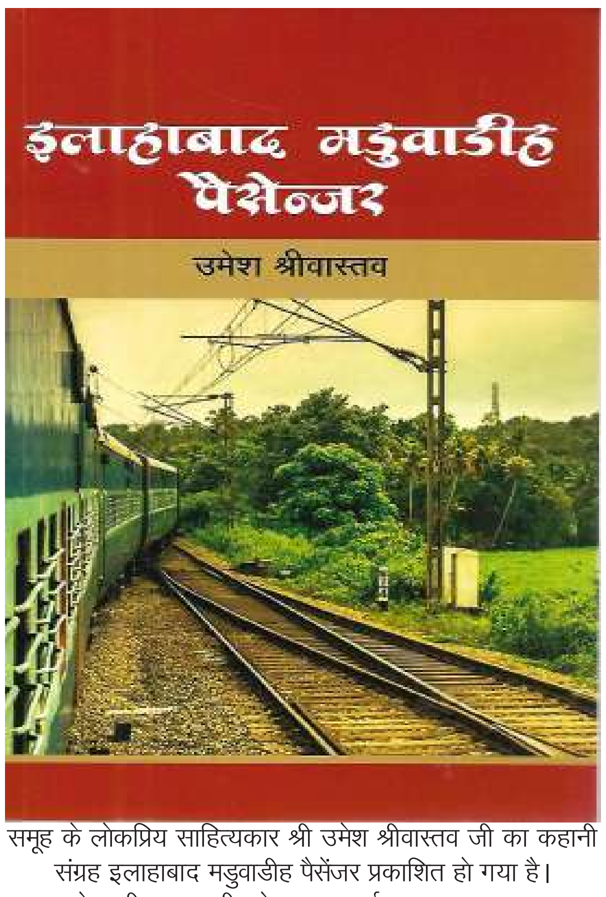

समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

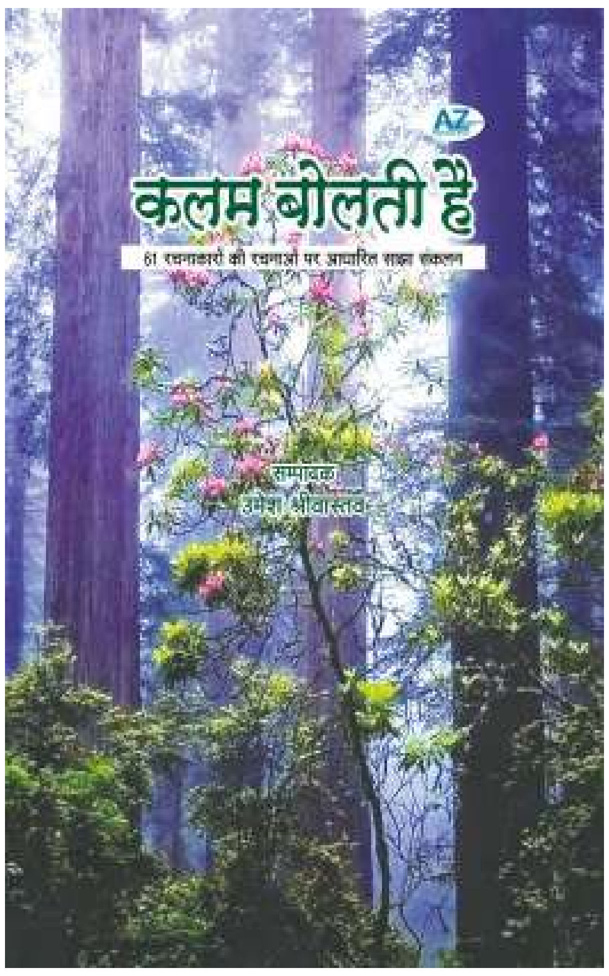

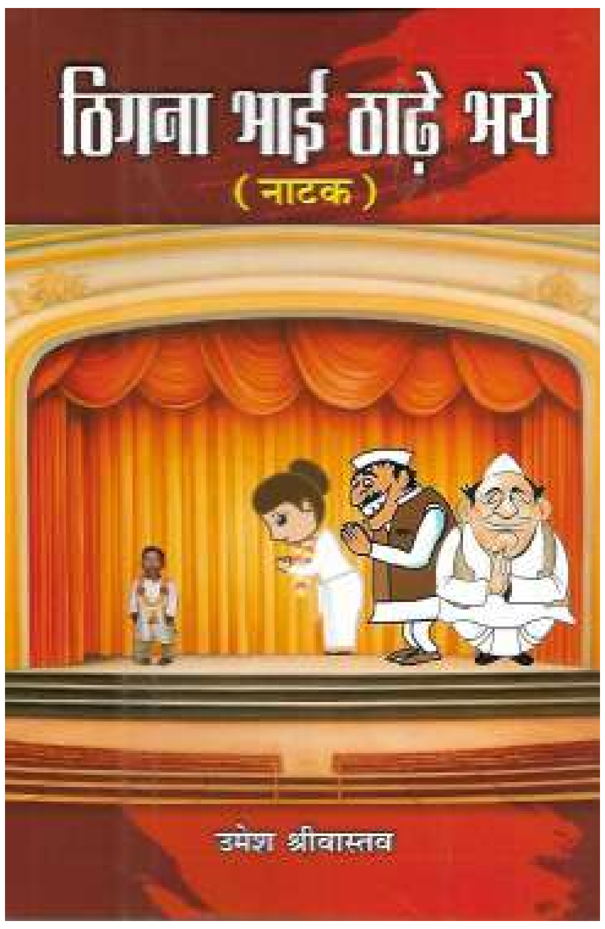

ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

संक्षिप्त

मोबाइल नंबरों से संबंधित नया यूपीआई नियम होने वाला है लागू, जानें विस्तार से यहां

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए नए नियम बनाए हैं। ये नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, बैंकों और यूपीआई सेवा प्रदाताओं जैसे फोनपे, जीपे और पेटीएम को संख्यात्मक यूपीआई आईडी के लिए कुछ सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। एनपीसीआई के नए निर्देश के अनुसार, बैंक और पेमेंट सेवा प्रदाता (पीएसपी) अपने डेटाबेस को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची या डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। यह अपडेट कम से कम साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, जिससे यूपीआई लेनदेन में सुरक्षा और दक्षता में सुधार हो सके। इसका मकसद यह है कि पुराने या बदले हुए मोबाइल नंबरों की वजह से होने वाली यूपीआई लेनदेन में गलतियों को कम किया जा सके। दूरसंचार विभाग के नियमों के अनुसार, यदि किसी का मोबाइल नंबर बंद कर दिया गया है, तो उस नंबर को 90 दिनों के बाद किसी नए ग्राहक को मिल सकता है। आमतौर पर, यदि कोई उपभोक्ता तीन महीने तक अपने मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं करता है, तो दूरसंचार कंपनी उस नंबर को बंद कर देती है और बाद में उसे किसी अन्य ग्राहक को दे दिया जाता है। नए यूपीआई नियमों के अनुसार, यदि कोई मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो जाता है, तो उस नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी भी निष्क्रिय हो जाएगी। अगर यूजर का मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो जाता है, तो आप उस नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके कारण, उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंकों के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय और उपयोग में हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनपीसीआई ने धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए यूपीआई से "कलेक्ट पेमेंट्स" सुविधाओं को खत्म करना शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह प्रणाली केवल बड़े, सत्यापित व्यापारियों तक ही सीमित रहेगी, जबकि व्यक्ति–से–व्यक्ति भुगतान की सीमा 2,000 रुपये तक होगी।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 2031 तक 16.7 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा रेलवे, रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली। रेलवे ने 2031 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 2031 तक 16.7 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह पैसा स्टेशनों को अपग्रेड करने, फ्रेड कॉरिडोर बनाने, हाई स्पीड रेल परियोजनाओं और पटरियों के विद्युतीकरण पर खर्च होगा। इन परियोजनाओं से रेलवे को अपना परिचालन बढ़ाने की मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है, भारतीय रेलवे ने 2031 तक फ्रेट कॉरिडोर, एचएसआर और स्टेशन अपग्रेड में लगभग 16.7 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। प्रमुख परियोजनाओं में

1,309 स्टेशनों का पुनर्विकास और डीएफसी का विस्तार शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे 1,309 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के विस्तार को प्राथमिकता दे रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ रही है। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) जैसी प्रमुख कंपनियां इन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल कर रही हैं। इस निवेश का एक प्रमुख उद्देश्य रेलवे की गति और दक्षता में सुधार करना है। सरकार लॉजिस्टिक्स बढ़ाने और परिवहन लागत को कम करने के लिए नए एचएसआर कॉरिडोर और अतिरिक्त डीएफसी के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 21 में परिव्यय 1.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में अनुमानित 2.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस अवधि में 14 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने स्टेशन उन्नयन के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (म्च्ब्) का मार्ग चुना है। फरवरी 2024 तक 508 स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है, जबकि शेष स्टेशनों का निर्माण चरण अभी शुरू होना बाकी है। इसी महीने सरकार ने 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की भी नींव रखी, जिससे 190 अरब रुपये का व्यावसायिक अवसर सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश की विशाल योजना से आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण हो सकता है। इससे यात्री अनुभव और माल परिवहन दक्षता में भी सुधार होने की उम्मीद है।

शेयर बाजार में सात दिनों से जारी बढ़त पर ब्रेक, सेंसेक्स 729 अंक टूटा, निफ्टी 23500 के नीचे

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक पिछले सात दिनों की बढ़त के बाद बुधवार को लाल निशान पर बंद हुए। हफ्ते तीसरे कारोबारी दिन 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 728.69 अंक गिरकर 77,288.50 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, 50 शेयरों का सूचकांक एनएसई निफ्टी 181.80 अंक गिरकर 23,486.85 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 85.69 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुआ।

संक्षिप्त

ट्रंप सरकार में भारतीय कनेक्शन और मजबूत, कौन हैं जय भट्टाचार्य? जिन्हें हेल्थ एजेंजी का हेड बनाया गया

भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को संयुक्त राज्य अमेरिका में अग्रणी स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण निकाय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें पिछले साल नवंबर में तत्कालीन राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 18वें NIH निदेशक के

रूप में नामित किया गया था। अमेरिकी सीनेट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, स्वास्थ्य नीति में विशेषज्ञता प्राप्त स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भट्टाचार्य ने मंगलवार को 119वीं कांग्रेस के प्रारंभिक रोल कॉल सत्र के दौरान 53-47 मतों के साथ यह पद हासिल किया।

एनआईएच निदेशक के रूप में जय भट्टाचार्य की भूमिका केंटकी से अमेरिकी सीनेटर मिच मैककोनेल ने एक्स पर कहा कि आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का नेतृत्व करने के लिए डॉ. जय भट्टाचार्य की पुष्टि के लिए मतदान किया गया। चिकित्सा अनुसंधान में व्यापक पृष्ठभूमि के साथ, मुझे उम्मीद है कि जय भट्टाचार्य में अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, वेबसाइट ने कहा कि अपनी नई भूमिका में, भट्टाचार्य नव नियुक्त अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के साथ मिलकर एनआईएच को चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी स्थिति में वापस लाएंगे। मंगलवार को एक बयान में, स्टैनफोर्ड मेडिसिन ने भट्टाचार्य को उनकी नियुक्ति पर गर्व से बधाई दी और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की कहा। एक संस्थान के रूप में, हम एनआईएच के मिशन के कट्टर समर्थक हैं, जो चिकित्सा ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और स्वास्थ्य सुधार के लिए नई संभावनाओं को खोलता है।

जय भट्टाचार्य कौन हैं?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले के नामांकन बयान के अनुसार, भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति के प्रोफेसर हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में एक शोध सहयोगी हैं, और स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, स्टैनफोर्ड फ्रीमैन स्पोगली इंस्टीट्यूट और हूवर इंस्टीट्यूशन में एक वरिष्ठ साथी हैं। वह स्टैनफोर्ड के सेंटर फॉर डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजिंग का भी निर्देशन करते हैं और उनका शोध सरकारी कार्यक्रमों, बायोमेडिकल इनोवेशन और अर्थशास्त्र की भूमिका पर जोर देता है।

यूक्रेन और रूस के साथ बातचीत में काला सागर में सुरक्षित नौवहन पर सहमति बनी :अमेरिका

मेरिका ने कहा कि काला सागर में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के लिए रुस और यूक्रेन के बीच सहमति बन गई है। अमेरिका ने मंगलवार को सऊदी अरब में यूक्रेन और रूस के

प्रतिनिधिमंडलों के साथ शांति की दिशा में संभावित कदमों पर तीन दिनों की वार्ता पूरी की। अमेरिका ने कहा है कि दोनों पक्ष "सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने तथा काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के प्रयोग को रोकने पर सहमत हुए हैं।

100 हेलीकॉप्टर, 9 हजार बचावकर्मी, दक्षिण कोरिया के जंगल में लगी आग ने मचाया कोहराम

दक्षिण कोरिया तीन तरफ से समुंदर से घिरा है। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी भाग में सेंचियोंग नामक एक इलाका है। ये क्षेत्र गांजे की पत्तियों से अलग अलग प्रयोगों के लिए चर्चा में रहता है। मसलन पत्तियों से कपड़े बनाना या घरों की छत बनाने में करना। इसी सेंचियोंग नामक इलाके के जंगलों में आग लग गई। आग जल्द ही आसपास के इलाकों में भी पहुंची। अब तक इसमें जलकर चार लोगों की मौत हो चुकी है। कई घायल हैं। आग अब तक करीबन 16 हजार एकड़ में फैल चुकी है। करीब डेढ़ हजार लोग घर छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 हजार से ज्यादा कर्मचारी और 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन तेज और सूखी हवाएं आग को बढ़ा रही हैं। योनहाप न्यूज ने बताया कि सप्ताहांत में दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में जंगल में लगी आग के फैलने के बाद कम से कम चार अग्निशामकों की मौत हो गई और 1,500 लोगों को निकाला गया, जिसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने आग पर काबू पाने के लिए ष्पूरी ताकत सेष् प्रयास करने का आह्वान किया।

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र
शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र
मोबाईल नम्बर 9190052 39332
9194504822227

भारत आदर्श...हिंदुस्तान का नाम लेते हुए ट्रंप ने अमेरिकी सिस्टम में क्या सुधार का ऐलान कर दिया

चुनावी प्रक्रिया को नया रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को संघीय चुनावों के लिए कड़े उपायों को पेश करते हुए एक व्यापक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। निर्देश में कहा गया है कि लोगों को संघीय चुनावों में मतदान करने के लिए पंजीकरण करने के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, आदेश में मतपत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समय सीमा लागू की गई है, जिसमें चुनाव के दिन तक सभी वोट प्राप्त होने की आवश्यकता है। ट्रम्प के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा लागू करने में विफल रहा है और राज्यों से मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ काम करने का आह्वान किया। ट्रम्प ने भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक स्व-सत्यापन पर निर्भर है। जर्मनी और कनाडा में मतों की गणना करते समय कागजी मतपत्रों की आवश्यकता होती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कई तरीके हैं जिनमें अक्सर बुनियादी हिरासत सुरक्षा की कमी होती है।

क्या ट्रंप के इस कदम को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

इससे उन राज्यों से संघीय निधि वापस लेने की भी धमकी दी गई है, जहां चुनाव अधिकारी इसका अनुपालन नहीं करते हैं। यह कदम चुनाव प्रक्रियाओं के खिलाफ ट्रम्प के लंबे इतिहास के अनुरूप है। वह अक्सर दावा करते हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, परिणाम सामने आने से पहले ही, और उन्होंने कुछ मतदान विधियों के खिलाफ़ लड़ाई छेड़ दी है, जब से वह 2020 का चुनाव डेमोक्रेट जो बिडेन से हार गए थे और उन्होंने इसे व्यापक धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाया था। ट्रंप ने विशेष रूप से मेल वोटिंग पर ध्यान केंद्रित किया है, बिना सबूत के तर्क दिया है कि यह असुरक्षित है और धोखाधड़ी को आमंत्रित करता है, जबकि उन्होंने इस मुद्दे पर अपना रुख बदल दिया है, क्योंकि रिपब्लिकन सहित मतदाताओं के बीच इसकी लोकप्रियता है। हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रम्प ने कहा कि आने वाले हफ्तों में और अधिक चुनाव कार्रवाई की जाएगी।

मोदी-जिपनिंग मिलकर करने वाले हैं बड़ा खेल ? ट्रूडो तो गए लेकिन अब क्यों परेशान है कनाडा

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में आने के साथ ही कनाडा में जबरदस्त खलबली मच चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नए प्रधानमंत्री की घोषणा हो गई। इधर नए प्रधानमंत्री ने चुनावों का ऐलान कर दिया। अब चुनावों का जिक्र हो और हर बार की तरह कनाडा इस बार भी अपने पुराने राग को न अलापे ऐसा कैसे हो सकता था। कनाडा ने इस बार भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। एक बार फिर कनाडा के आरोपों वाली लिस्ट में टॉपर पर चीन और भारत का नाम है। कनाडा का मानना है कि उसके देश में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए चीन और भारत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बता दें कि 24 अप्रैल को कनाडा में आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही कनाडा ने भारत का नाम लेकर रोना शुरू कर दिया।

आम चुनाव में भारत कर सकता है हस्तक्षेप

कनाडा की खुफिया एजेंसी की उप निदेशक वनेसा लॉयड ने दावा किया है कि कनाडा के आम चुनाव में भारत हस्तक्षेप कर सकता है। वनेसा ने कहा कि भारत के पास कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की मंशा और क्षमता दोनों है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी कनाडा के खिलाफ अपनी रणनीतिक नीतियों के अनुसार दखल दे सकता है। लॉयड ने चुनावी सुरक्षा पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत कनाडा में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। लॉयड ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कुछ देशों ने 2022 के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलीएवरे के चुनाव में धन जुटाने और समर्थन हासिल करने में भूमिका निभाई थी।

चीन एआई की मदद से अपने पक्ष में नैरेटिव बना रहा

वनेसा ने यह भी कहा कि चीन एआई की मदद से अपने पक्ष में नैरेटिव बना रहा है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपने अनुकूल नैरेटिव बना सकता है। रूस अपने प्रचार तंत्र और बॉट आर्मी के जरिए कनाडाई मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति बना रहा है। रूस पर बीते चुनाव में भी हस्तक्षेप करने का आरोप लगा था।

अमेरिकी चुनाव की किस प्रक्रिया को भारत जैसा करना चाहते हैं ट्रंप, यूएस में ये कितना मुश्किल ?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की संघीय चुनाव प्रक्रिया को बदलने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। अपने इस आदेश में ट्रंप ने कई बदलावों की बात कही है। खासकर मतदाताओं के सत्यापन से जुड़े नियमों में, वोट डालने की प्रक्रिया में, मतों को गिनने की प्रक्रिया में और वोटिंग के तरीकों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा जारी है। मजेदार बात यह है कि ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भारत का भी जिक्र है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव कराना चाहते हैं? इन बदलावों के पीछे उनका तर्क क्या है? ट्रंप ने अपने आदेश में भारत का जिक्र क्यों किया और वह किस प्रक्रिया को भारत की तर्ज पर करना चाहते हैं? इसके अलावा ट्रंप के लिए अमेरिका में ऐसा करना कितना मुश्किल होने वाला है? आइये जानते हैं...

पहले जानें- ट्रंप के कार्यकारी आदेश में भारत का जिक्र कहां?

गौरतलब है कि ट्रंप कई मौकों पर भारत की वोटिंग प्रक्रिया की तारीफ कर चुके हैं। उनके हालिया कार्यकारी आदेश में भी भारत से प्रभावित होने की बात सामने आती है। ट्रंप ने आदेश में एक जगह पर भारत का जिक्र भी किया है। आदेश में भारत और ब्राजील को उन्नत मतदाता पहचान प्रणाली लागू करने वाले देशों के उदाहरण तौर पर दिखाया गया।

अब जानें- अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया में क्या बदलाव चाहते हैं ट्रंप?

1. मतदाताओं को साबित करनी होगी अमेरिकी नागरिकता

क्या है फैसला?

ट्रंप की तरफ से जारी कार्यकारी आदेश में सबसे अहम आदेश मतदाताओं को लेकर है। इसमें कहा गया है कि संघीय चुनाव में मतदान का अधिकार सिर्फ ष्अमेरिका के नागरिकोंष् को ही होना चाहिए। इसलिए गैर-अमेरिकियों की वोटिंग रुकवाने के लिए (जो कि पहले से ही अवैध है और इस पर आपराधिक मुकदमा और निर्वासन जैसी कार्रवाई की जा सकती है) अब आदेश के तहत मतदाताओं को वोटिंग के लिए पंजीकरण के दौरान अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी सबूत मुहैया कराना होगा। इस दस्तावेज में पासपोर्ट शामिल हो सकता है। आदेश में कहा गया है कि अमेरिका की सभी संघीय एजेंसियां, जैसे- डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और विदेश मंत्रालय अपने डाटा को चुनाव अधिकारियों के साथ साझा करेंगे और राज्यों की चुनाव सूची में शामिल गैर-अमेरिकियों की पहचान में मदद करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी आदेश में चुनाव सहायता आयोग (इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन) से कहा गया है कि संघीय चुनाव में वोट करने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन के वक्त सरकार की तरफ से जारी पहचान पत्र मुहैया कराना होगा। इसके अलावा राज्य और स्थानीय अधिकारियों से मतदाताओं के पहचान पत्र के आधार पर ही उनकी पूरी जानकारी सत्यापित करने के लिए कहा गया है।

आदेश को लागू कराने में क्या समस्या?

ट्रंप की तरफ से जारी इस आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। मताधिकार से जुड़े समूहों का कहना है कि मतदान से पहले अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देने की अनिवार्यता से कई लोगों से वोटिंग का अधिकार छिन सकता है। 2023 की ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस एंड अदर ग्रुप्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में वोटिंग के लिए सक्षम 9 फीसदी लोगों यानी करीब 2.13 करोड़ लोगों के पास सरकार द्वारा जारी नागरिकता का प्रमाणपत्र मौजूद नहीं रहता है। ऐसे में यह लोग प्रमाणपत्र जुटाने की जगह वोटिंग में हिस्सा न लेने के विकल्प को अपना सकते हैं। दूसरी तरफ कई महिलाएं, जो शादी के बाद अपना नाम बदल लेती हैं, उन्हें भी वोटिंग के लिए रजिस्टर कराने में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि उनके सरकारी दस्तावेजों में उनका शादी से पहले का नाम ही लिखा होता है। हाल ही में अमेरिका के न्यू हैंपशर में हुए चुनावों में शादीशुदा महिलाओं को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

भारत से क्या प्रेरणा?

डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं के सत्यापन को लेकर भारत का उदाहरण दिया। दरअसल, भारत में वोटिंग के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं वोटिंग के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखे जाने के साथ-साथ पेपर ट्रेल में भी रखे जाते हैं। ऐसे में भारत में वोटिंग प्रणाली समय के साथ पारदर्शी बनी है। दूसरी तरफ अमेरिका में वोट करने के लिए नागरिकों को किसी संघीय सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र को सत्यापित कराने के बाद वोटिंग कराने की अनिवार्यता नहीं थी। दरअसल, अमेरिका में अलग-अलग राज्यों में लोगों के पास पहले राज्य की नागरिकता होती है। यानी वोटरों के पास राज्य में मतदान का अधिकार जन्म के साथ ही होता है और उन्हें इससे जुड़ा पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाता है। हालांकि, मतदान प्रक्रिया के लिए अमेरिका में अलग से कोई पहचान पत्र या संघीय पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ती।

ट्रंप का आरोप है कि राज्यों के इस नियम की वजह से कई बार डेमोक्रेट पार्टी द्वारा शासित राज्य शरणार्थियों को अपनी नागरिकता देकर वोट डालने की इजाजत देते हैं। हालांकि, उनके इन आरोपों को लेकर अब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं।

2. चुनाव के दिन ही डाले जाएं वोट, ईमेल बैलट भी चुनाव के दिन तक ही मान्य हों

क्या है आदेश?

ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में एक ही दिन में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। यानी जिस दिन पूरे देश में मतदान किया जा रहा हो, वह उसी दिन पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही पोस्टल बैलट को स्वीकार करने का आखिरी दिन भी मतदान का दिन ही होना चाहिए और वोटों की गिनती शुरू होने के बाद पोस्टल बैलट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मौजूदा समय में अमेरिका के 18 राज्यों में यह नियम है कि वह मतदान के लिए तय दिन के बाद भी पोस्टल बैलट या मेल के जरिए वोट्स को स्वीकार कर सकते हैं। बस उस पोस्टल बैलट में तारीख वोटिंग के दिन या इससे पहले की होनी चाहिए। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह वोट चुनाव अधिकारियों के पास कितने दिन बाद पहुंचा।

रूस ने आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए यूक्रेनियों को दोषी ठहराया, कीव ने बताया दिखावा

मॉस्को, एजेंसी। रूस की तरफ से बुधवार को यूक्रेन में लड़ाई के दौरान आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किए गए 23 यूक्रेनियों को दोषी ठहराया है। वहीं रूस के इस फैसले की यूक्रेन की तरफ से निंदा की गई है और इसे दिखावा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया गया है।

अभियुक्तों में कौन-कौन शामिल?

मामले में रूसी मीडिया रिपोर्टों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, अभियुक्तों में विशेष आजोव ब्रिगेड के 14 वर्तमान या पूर्व लड़ाके शामिल थे, जिसे रूस ने आतंकवादी समूह घोषित किया है। इसमे कुल नौ महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे, जो

रसोइये या सहायक कर्मी के रूप में काम करते थे। इनमें से 12 आरोपी अदालत में मौजूद नहीं थे। 11 को पहले ही युद्धबंदियों की अदला-बदली के तहत यूक्रेन वापस भेजा जा चुका था, जबकि एक आरोपी की 2023 में जेल में मौत हो गई थी।

रूस ने सभी पर क्या लगाए थे आरोप?

रूस ने इन सभी पर हिंसक तख्तापलट की साजिश और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। कुछ पर आतंकवादी हमले की ट्रेनिंग लेने का भी आरोप था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रूसी मानवाधिकार संगठन ष्मेमोरियलष् ने सभी दोषियों को राजनीतिक कैदी करार दिया है। वहीं, यूक्रेन के मुताबिक, इनमें से कई लोगों को 2022 में मारियुपोल शहर में पकड़ा गया था, जब वे अजोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना के खिलाफ डटे हुए थे। कुछ को तब गिरफ्तार किया गया जब वे शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

इधर, यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त, दिमित्रो लुबिनेट्स ने इस मुकदमे को रूस का दिखावटी नाटक बताया। उन्होंने कहा, रूस और न्याय का कोई संबंध नहीं है। जो असली अपराधी हैं, वे नहीं बल्कि अपने देश की रक्षा करने वाले लोग कटघरे में खड़े हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस फैसले पर सख्त प्रतिक्रिया देने की अपील की है।

गाजा में दिखा चौंकाने वाला नजारा, फलस्तीनियों ने हमास के खिलाफ किया प्रदर्शन; जंग खत्म करने की अपील

पीटीआई, गाजा/काहिरा। गाजा पट्टी में युद्ध-विरोधी विरोध प्रदर्शन के दौरान फलस्तीनियों ने हमास के खिलाफ नारे लगाए। यह चरमपंथी समूह के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश का दुर्लभ मामला था। दावा किया जा रहा है कि संगठन ने लंबे समय से लोगों की असहमति को दबा रखा है। हमास इस्राइल के साथ 17 महीने से जारी जंग के बाद भी इस क्षेत्र पर शासन कर रहा है। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में सैकड़ों लोगों को मंगलवार को उत्तरी शहर बेत लाहिया में भारी तबाही वाले युद्ध-विरोधी विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।